Website : www.mantrabharat.com
जुनून है सच लिखने का
E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 254
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
शनिवार, 20 सितम्बर, 2025

मंत्र भारत
हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 कुंभ मेले के मद्देनजर शिरडी हवाई अड्डे पर ... 4 राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर पॉश एक्ट.... 7 'जहां देखों कंगना रनौत को थप्पड़ मारो', ...

आज पीएम मोदी का मुंबई दौरा, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर (शनिवार) को अत्याधुनिक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 20 सितंबर को 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गुजरात भी जाएंगे और भावनगर में सुबह लगभग 10:30 बजे 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, साथ ही सभा को भी संबोधित करेंगे।

इसके बाद, प्रधानमंत्री धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दोपहर लगभग 1:30 बजे, वह एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा करेंगे। समुद्री क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री 7,870 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली समुद्री क्षेत्र से संबंधित कई विकास परियोजनाओं

का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह इंदिरा डॉक पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता में एक नए कंटेनर टर्मिनल और संबंधित सुविधाओं; पारादीप बंदरगाह पर एक नए कंटेनर बर्थ, कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं और संबंधित विकास कार्यों; और टूना टेकरा मल्टी-कार्गो टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री एन्नोर में कामराजर बंदरगाह पर अग्निशमन सुविधाओं और आधुनिक सड़क संपर्क और चेन्नई बंदरगाह पर समुद्री दीवारों और रिवेटमेंट सहित तटीय सुरक्षा कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अतिरिक्त, कार निकोबार द्वीप पर एक समुद्री दीवार निर्माण, कांडला के दीनदयाल बंदरगाह पर एक बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ और हरित बायोमेथेनॉल संयंत्र, और पटना एवं वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाओं की भी आधारशिला रखी जाएगी।

समग्र और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकार की 26,354 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे छारा बंदरगाह पर एचपीएलएनजी पुनर्गैसीकरण टर्मिनल, गुजरात आईओसीएल रिफाइनरी में एक्रिलिक और ऑक्सो अल्कोहल परियोजना, 600 मेगावाट ग्रीन शू पहल, किसानों के लिए पीएम-कुसुम 475 मेगावाट कंपोनेंट सी सौर फीडर, 45 मेगावाट बडेली सौर पीवी परियोजना और धोरडो गांव के पूर्ण सौरीकरण सहित अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

सीट बंटवारे की खींचतान के बीच पटना में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, CWC की अहम बैठक

पटना। कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की विस्तारित बैठक 24 सितंबर को पटना में होगी। यह बैठक आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारियों का एक प्रतीकात्मक मंच है, संयोग से यह बैठक महागठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा, गांधी परिवार, एआईसीसी महासचिव, तीन मुख्यमंत्री भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग लेंगे, जिसमें बिहार के भविष्य के लिए कांग्रेस के दृष्टिकोण, मोदी सरकार के खिलाफ पार्टी की रणनीति, विशेष गहन पुनरीक्षण और वोट चोरी के खिलाफ मुद्दों पर प्रकाश डालने की उम्मीद है।

पार्टी पदाधिकारियों का मानना है कि बिहार की राजधानी में शीर्ष कांग्रेस नेताओं के एकत्र होने से हाल ही में राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव द्वारा अन्य भारतीय ब्लॉक नेताओं के साथ की गई 'मतदाता अधिकार यात्रा' के प्रभाव को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित करने का निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब कांग्रेस पर अपने सहयोगियों की ओर से पिछले चुनाव में लड़ी गई 70 सीटों की तुलना में 10-15 कम सीटों पर समझौता करने का दबाव है, जिसका पार्टी नेतृत्व विरोध करने की कोशिश कर रहा है।

बिहार कांग्रेस इकाई ने उन सीटों के लिए

संभावित उम्मीदवारों पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिन पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया इस महीने के अंत में एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी को सौंप दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस ने मंगलवार को अपनी प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया, जिसमें बिहार इकाई के प्रमुख राजेश राम, शकील अहमद खान और मदन मोहन झा जैसे नेता शामिल हैं, ताकि चुनावों की तैयारी की जा सके।

संक्षिप्त न्यूज

पीयूष गोयल ने अबू धाबी में बढ़ाई भारत की आर्थिक कूटनीति, निवेश संबंध मजबूत करने पर जोर

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अबू धाबी के उप शासक शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की और उभरती प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे में निवेश और ऊर्जा सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। अबू धाबी के उप शासक द्वारा एक्स पर लिखे गए एक पोस्ट के अनुसार, बैठक में भारत-यूएई रणनीतिक साझेदारी की बढ़ती गहराई को रेखांकित किया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने नवाचार आधारित सहयोग और मजबूत निवेश संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। शेख तहनून ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैंने भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, महामहिम पीयूष गोयल से मुलाकात की, जहाँ हमने नवीनतम आर्थिक और तकनीकी रुझानों, उत्पादकता बढ़ाने और विकास को गति देने में एआई की भूमिका, साथ ही बुनियादी ढाँचे में निवेश और ऊर्जा सुरक्षा के अवसरों पर चर्चा की। हमने नवाचार, बुनियादी ढाँचे में निवेश और प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग के माध्यम से यूएई-भारत साझेदारी को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

चर्चा की दूरदर्शी प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए, बैठक के बाद, एक्स पर एक पोस्ट में, गोयल ने उन अनगिनत अवसरों का उल्लेख किया जिन पर दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं, जिनमें बुनियादी ढाँचा, ऊर्जा सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। गोयल ने कहा कि महामहिम, आपसे मिलकर मुझे सम्मान मिला। हमारे देशों के लिए एआई, ऊर्जा सुरक्षा और बुनियादी ढाँचे सहित रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग करने के अपार अवसर हैं।

सीएम धामी ने दिया 'सेवा पखवाड़ा' का मंत्र, जनसेवा व आपदा राहत को लेकर जताई प्रतिबद्धता

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को 'सेवा पखवाड़ा' कार्यक्रम के अंतर्गत देहरादून नगर निगम द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पूरे राज्य में स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जनसेवाओं को उपलब्ध कराने और केंद्र व राज्य

सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुउद्देश्यीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी से सेवा पखवाड़ा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने हस्तशिल्प उत्पादों के विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और 11 कारीगरों को उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तराखंड की बुनाई और हस्तशिल्प परंपराएँ अपनी विविधता, पारंपरिक डिज़ाइन और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं।

मणिपुर में अर्धसैनिक बल के ट्रक पर घात लगाकर हमला, एक जवान शहीद, तीन घायल

इंफाल। मणिपुर के बिष्णुपुर में अर्धसैनिक बल के एक वाहन पर हथियारबंद लोगों के हमले में असम राइफल्स का एक जवान शहीद हो गया। यह घटना शुक्रवार शाम करीब 6 बजे जिले के नाम्बोल सबल लेइकाई इलाके में हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बंदूकधारियों के एक समूह ने उस वाहन पर घात लगाकर हमला

किया जिसमें असम राइफल्स के जवान इम्फाल से बिष्णुपुर जिले की ओर जा रहे थे। हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। असम राइफल्स के जवान इम्फाल से एक 407 टाटा वाहन में यात्रा कर रहे थे, जब शाम करीब 6 बजे नाम्बोल पुलिस थाना क्षेत्र में यह हमला हुआ। बंदूकधारियों के एक समूह ने उस वाहन पर घात लगाकर हमला किया जिसमें असम राइफल्स के जवान इम्फाल से बिष्णुपुर जिले की ओर जा रहे थे। इस हमले में एक जवान की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया। सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुँच गए हैं और आगे की जाँच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।

जम्मू में किसानों का दर्द देख भावुक हुए शिवराज! बोले- संकट से उबारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे

श्रीनगर।केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर किसानों को हुए फसल नुकसान का आकलन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सहायता प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यहाँ पत्रकारों को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि आज मैं जम्मू-कश्मीर की जनता और किसानों का एक विनम्र सेवक बनकर आया हूँ। हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा ने फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया है। केंद्र सरकार की एक टीम भी यहाँ भेजी गई थी। लेकिन मुझे किसानों के नुकसान को व्यक्तिगत रूप से देखने की ज़रूरत महसूस हुई। मुझे प्रभावित किसानों से बातचीत करनी चाहिए। और फिर, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, हम किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

शिवराज ने आगे कहा कि संकट बहुत बड़ा है। जब फसलें नष्ट होती हैं, तो न केवल फसलें नष्ट होती हैं, बल्कि किसान का जीवन भी बर्बाद होता है। उसके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। हालाँकि, किसानों को दुखी नहीं

होना चाहिए। हम इस संकट से उबरेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएँगे। मैं इसी संकल्प के साथ आया हूँ। मैं अब नुकसान का निरीक्षण करूँगा। जम्मू और कश्मीर लगातार भारी बारिश के बाद के हालात से जूझ रहा है। बुधवार को, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस साल मानसून ने व्यापक नुकसान पहुँचाया है और वादा किया कि राज्य सरकार केंद्र से पर्याप्त सहायता मांगेगी।

उमर अब्दुल्ला ने मेंढर उपखंड के कलाबन गाँव का दौरा करने के बाद कहा कि इस साल की बारिश ने जम्मू और कश्मीर में काफ़ी नुकसान पहुँचाया है... हम लोगों को राहत पहुँचाने के लिए अपने सभी वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। हम केंद्र सरकार के साथ भी लगातार संपर्क में हैं... हम जम्मू और कश्मीर के लिए एक बड़े पैकेज की माँग उनके सामने रखेंगे। सोमवार को, पुंछ ज़िले के कलाबन गाँव के लगभग 400 निवासियों को अस्थायी आश्रय स्थलों में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि कई दिनों तक लगातार बारिश के कारण ज़मीन धंसने के कारण कई घरों में दरारें आ गई थीं। गाँव को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और निवासियों को अगली सूचना तक घर खाली करने की सलाह दी गई है।

रिजिजू का बड़ा हमलाः राहुल गांधी ने वही कहानी गढ़ी जो पाकिस्तान गढ़ता है

नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और उन पर 'पाकिस्तानी बयान' दोहराने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणियों का इस्तेमाल अक्सर सीमा पार भारत-विरोधी समूहों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि हाल के वर्षों में कांग्रेस सांसदों का यह रवैया लगातार बना हुआ है, जिससे राष्ट्रीय विमर्श पर उनके बयानों के प्रभाव को लेकर चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जो भी बयान गढ़ता है, वही बयान भारत में राहुल गांधी और उनकी कंपनी द्वारा गढ़ा जाता है। इसलिए हमने पिछले कुछ वर्षों में महसूस किया है कि राहुल गांधी और उनका वामपंथी समूह भारत में जो भी बोलते हैं और जो भी बयान गढ़ने की कोशिश करते हैं, वही बात पाकिस्तान में भारत-विरोधी समूहों और तत्वों द्वारा इस्तेमाल की जाती है।

नायब सैनी सरकार ने गुरुग्राम को गुंडों का शहर बना दिया, रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर निशाना साधा

गुरूग्राम। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए उन पर गुड़गांव और पूरे राज्य में अपराध बढ़ने देने का आरोप लगाया।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और उन्होंने लोगों से मौजूदा सरकार को हटाने का आग्रह किया। हरियाणा के लोगों की जुबानी, गुरुग्राम गैंग्स की असली कहानी! कल गुरुग्राम के सेक्टर 45 में जो हुआ आज आप सबके साथ भी हो सकता है। सुरजेवाला ने कहा कि अब पूरा हरियाणा कह रहा है मुख्यमंत्री और डीएम प्रशासन के मुखौटे मात्र हैं। हरियाणा में माफियाओं और रंगदारी वसूलने वालों का राज है। अब चुप रहना गुनाह है। अब चुप रहना गुनाह है। उठो, बोलो, भाजपा के नायब सैनी से जवाब मांगो।

उन्होंने एक वीडियो संदेश भी पोस्ट किया जिसमें जनता से मौजूदा सरकार को हटाने की अपील की गई। कांग्रेस

सांसद ने कहा, नायब सैनी और भाजपा सरकार ने गुड़गांव को गुंडों का शहर बना दिया। गैंग्स ऑफ़ गुड़गांव अब मिलेनियम सिटी गुड़गांव का नाम है, जिसे कांग्रेस ने बड़ी मेहनत से बनाया था। पुराने ज़माने में एक फिल्म आई थी, 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई'। नायब सैनी और भाजपा सरकार ने अब गुड़गांव को गुंडों का शहर बना दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सेक्टर 45 में हाल ही में हुए हमले में इमारतों और कारों पर गोलियों के निशान पड़ गए हैं। उन्होंने पिछले हफ़्ते एक ओवरपास के नीचे एक विदेशी का शव मिलने का भी ज़िक्र किया और कहा कि ऐसी घटनाओं ने जनता का विश्वास हिला दिया है। कल सेक्टर 45 में जो हुआ, जिस तरह एमएनआर बिल्डिंग पर गुंडों ने अंधाधुंध फायरिंग की, पूरी बिल्डिंग पर गोलियों के निशान हैं। गाड़ियों पर भी गोलियों के निशान हैं। गुंडों का आलम ये है कि बेखौफ गुंडे रंग मांगते हैं, हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं।

ममता बनर्जी की भाभी की कॉलेज अध्यक्ष नियुक्ति न्यायिक जांच के घेरे में, एचसी ने दिए संकेत

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाभी, कजरी बनर्जी की रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पद के लिए शिक्षा के क्षेत्र से किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। अंतरिम राहत प्रदान करते हुए, न्यायालय ने कॉलेज की प्रिंसिपल श्राबंती भट्टाचार्य के खिलाफ कजरी बनर्जी द्वारा 3 जुलाई को जारी किए गए नोटिस और 29 अगस्त को जारी

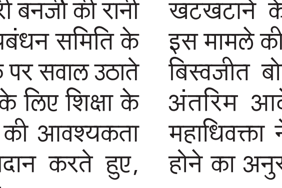

निलंबन आदेश पर आठ सप्ताह के लिए रोक लगा दी। साथ ही, न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि उनकी नियुक्ति की वैधता की न्यायिक जाँच की आवश्यकता है। अदालत ने समिति अध्यक्ष के रूप में कजरी बनर्जी की नियुक्ति पर भी संदेह जताया और कहा कि इस मुद्दे पर छह सप्ताह में फिर से सुनवाई की जाएगी।

यह ताज़ा घटनाक्रम भट्टाचार्य द्वारा कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद सामने आया है। इस मामले की पहली सुनवाई न्यायमूर्ति बिस्वजीत बोस ने की, जिन्होंने एक अंतरिम आदेश जारी किया। जब महाधिवक्ता ने उनसे मामले से अलग होने का अनुरोध किया, तो न्यायमूर्ति बोस ने नाराजगी व्यक्त की, लेकिन बाद में अपने कदम वापस ले लिए। बाद में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की पीठ ने की। उसी दिन न्यायाधीश ने प्रबंध समिति के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर लिए गए निर्णय पर अस्थायी रोक लगा दी।

न्यायाधीश ने कहा कि 2017 के कानून के अनुसार, कॉलेज का प्रबंधन गठित करने के बजाय, प्रबंध समिति का संचालन राज्य सरकार द्वारा नामित पाँच लोगों द्वारा किया जा रहा है। न्यायाधीश ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है।

लालू परिवार में बढ़ी वर्चस्व की जंग, तेजस्वी के करीबी को रोहिणी आचार्य ने दिखाया आईना!

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार में लंबे समय से राज्यसभा सदस्य संजय यादव के खिलाफ चल रहा विरोध खुलकर सामने आ गया, जब उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। इसकी आग परिवार को और झुलसा सकती है, राजद और उसके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की छवि को नुकसान पहुँचा सकती है, और आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी संभावनाओं को भी नुकसान पहुँचा सकती है।

लालू पहले ही अपने बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव से अलग हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने शादीशुदा होने के बावजूद एक लड़की के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध होने की बात स्वीकार की थी। रोहिणी द्वारा शेयर की गई पोस्ट पटना के आलोक कुमार ने लिखी थी। इसमें संजय एक छोटी बस की अगली सीट पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे वैनिटी वैन में बदल दिया गया है और जिसका इस्तेमाल लालू के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी बिहार अधिकार यात्रा के लिए कर रहे हैं।

रोहिणी द्वारा शेयर की गई आलोक की पोस्ट में लिखा है, 'आगे की सीट हमेशा शीर्ष नेता के लिए होती है और उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को उस पर नहीं बैठना चाहिए। हालाँकि, अगर कोई खुद को शीर्ष नेतृत्व से ऊपर समझता है तो यह अलग बात है।' इसमें आगे कहा गया है कि 'हम समेत पूरा बिहार लालू जी और तेजस्वी यादव को आगे की सीट पर बैठे देखने का आदी है। उस पर किसी और का बैठना हमें बिल्कुल अस्वीकार्य है। यह उन चापलूसों के लिए अलग बात है जो एक घटिया व्यक्ति में एक उल्लेखनीय रणनीतिकार, सलाहकार और रक्षक देखते हैं।'

हालाँकि यह तस्वीर किस तारीख को खींची गई, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन तेजस्वी ने 16 सितंबर को बिहार अधिकार यात्रा शुरू की थी। पाँच दिवसीय यह यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर लगभग 10 जिलों से होते हुए 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी।

फेसबुक पोस्ट से संकेत मिलता है कि राजद में, खासकर लालू परिवार में, संजय का विरोध बढ़ रहा है। लालू की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती और बड़े बेटे तेज प्रताप लंबे समय से तेजस्वी पर उनके प्रभाव और मौजूदगी के विरोधी माने जाते रहे हैं।

सर्वेक्षण रद्द किया जाए या नहीं? मंत्रियों की आपत्ति के बाद सिद्धारमैया ने की बैठक

बैंगलुरू। कर्नाटक में जाति जनगणना का भविष्य अधर में लटका हुआ है और आज इस पर फैसला आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुनः सर्वेक्षण होना चाहिए या नहीं, इस पर व्यापक असमंजस को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक कैबिनेट सत्र के बाद हुई है, जिसमें लिंगायत नेताओं सहित कुछ मंत्रियों ने सर्वेक्षण पर संदेह जताते हुए कड़ी आपत्ति जताई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री डीके सुकुमार और अन्य चुनिंदा मंत्री शामिल होंगे,और यह तय होगा कि सर्वेक्षण रद्द किया जाएगा या फिर से सर्वेक्षण कराया जाएगा। सरकार ने पहले घोषणा की थी कि यह सर्वेक्षण इस महीने की 22 तारीख से 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिससे आज मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक उत्सुकता का विषय बन गई है।

कैबिनेट चर्चाओं के दौरान, कई मंत्रियों ने कथित तौर पर कुछ जातियों के 'समस्याग्रस्त नामकरण' पर आपत्ति जताई, जिनमें 'कुरुबा ईसाई', 'ब्राह्मण ईसाई' और 'वोक्कालिगा ईसाई' जैसी दोहरी पहचान शामिल हैं। कुछ ने आगाह किया कि इन वर्गीकरणों का दुरुपयोग धर्मांतरण को बढ़ावा देने या अन्य ओबीसी समुदायों के आरक्षण में हिस्सेदारी को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि हमने चर्चा की है कि कैसे कुछ लोग और भाजपा स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कानून के दायरे में रहते हुए जनता की राय को ध्यान में रखते हुए एक सूची बनाई है। हम राय मांग रहे हैं। यह सर्वेक्षण सभी को न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा है।

कैबिनेट बैठक में कथित तौर पर वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा जैसे प्रभावशाली समुदायों की आपत्तियों पर चर्चा हुई, जिन्होंने खुद को हिंदू के बजाय एक अलग धर्म के रूप में पहचानने पर भ्रम या मतभेद व्यक्त किए हैं।

'चुनाव आयोग में शपथपत्र दाखिल करें...': राहुल के आरोपों पर शिंदे का पलटवार, कहा- सूची में गड़बड़ी का दावा गलत

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदाता सूची में गड़बड़ी संबंधी नए आरोपों को 'पूरी तरह निराधार' बताया है। शिंदे हुए उन्हें चुनौती दी कि वे चुनाव आयोग (ईसी) के समक्ष शपथपत्र दाखिल करें। राहुल गांधी ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 'लोकतंत्र को नष्ट करने वालों' की रक्षा करने का आरोप लगाया था और कर्नाटक की एक विधानसभा सीट का हवाला देकर दावा किया कि चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थकों के वोट व्यवस्थित तरीके से हटाए जा रहे थे। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को 'गलत और निराधार' बताया और कहा, किसी भी आम व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन वोट हटाना संभव नहीं है। गुरुवार देर रात पत्रकारों से बातचीत में एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के मतदाता हेरफेर संबंधी आरोप निराधार हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक की अलंद सीट पर उसी चुनाव प्रणाली के तहत जीत दर्ज की, जिस पर गांधी अब सवाल उठा रहे हैं। शिंदे ने पूछा, 'किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में वोट चोरी का आरोप कैसे लगाया जा सकता है, जहां कांग्रेस पार्टी खुद विजयी रही?

उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी को चुनाव प्रक्रिया पर शक है तो उन्हें चुनाव आयोग में शपथपत्र दाखिल करना चाहिए और उचित कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। केवल तभी उन्हें ऐसे गंभीर आरोप लगाने चाहिए। शिंदे ने कहा, मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया सख्त है और इसे न जल्दबाजी में किया जा सकता है, न मनमाने ढंग से। उन्होंने आगे दावा किया कि कांग्रेस सांसद की आलोचनाएं एक पैटर्न का हिस्सा हैं। जब भी राहुल गांधी चुनाव हारते हैं, वे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। कभी ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता, कभी मतदाता सूची और कभी चुनाव आयोग की।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही सबसे पहले चुनाव कराने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया गया था। तो अब केवल इसलिए यह दावा करना कि प्रणाली त्रुटिपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस हार गई है, अनुचित है।

शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा, एनसीपी और शिवसेना के महायुति गठबंधन को अभूतपूर्व समर्थन दिया है और पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों और लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं को पहचाना है। उन्होंने कहा, जनता के इस जनादेश को कमजोर करना और बिना सबूत आरोप लगाना जनता की पसंद का अनादर करने का प्रयास है।

बता दें कि राहुल गांधी ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की अलंद सीट में 6,018 वोट हटाने की कथित कोशिशों का हवाला दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र की राजौरा सीट का भी उदाहरण दिया। जहां कथित तौर पर 6,850 वोट 'धोखाधड़ी' से सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल करके जोड़े गए।

मध्य रेल के सोलापुर मंडल ने 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान 2025 के अंतर्गत वॉकथॉन का आयोजन किया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल के सोलापुर मंडल ने चल रहे 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान 2025 के अंतर्गत स्वच्छता और ज़िम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान के तीसरे दिन 19 सितंबर 2025 को एक वॉकथॉन का आयोजन किया। वॉकथॉन सुबह मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से शुरू हुआ और सोलापुर रेलवे स्टेशन पर समाप्त हुआ। DRM सोलापुर डॉ. सुजीत मिश्रा ने सभी प्रतिभागियों को स्वच्छता शपथ दिलाई और रैली को हरी झंडी दिखाई।

इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित लगभग 125 स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक, सोलापुर; मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रेलवे अस्पताल, सोलापुर; शाखा अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों और नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। रैली का नेतृत्व सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर और सहायक सुरक्षा आयुक्त ने अपनी टीमों के साथ प्रभावी ढंग से किया।

इस अवसर पर बोलते हुए, डीआरएम सोलापुर डॉ. सुजीत मिश्रा ने रेलवे कर्मचारियों और आम जनता से श्रमदान (स्वैच्छिक सेवा) में भाग लेकर और कचरे के निपटान के लिए कूड़ेदानों का उपयोग करने की आदत डालकर स्वच्छता में सक्रिय योगदान देने की अपील की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्वच्छता केवल रेलवे की ही ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की साझा प्रतिबद्धता भी है।

वॉकथॉन ने एक जन जागरूकता कार्यक्रम के रूप में कार्य किया, जिसने रेलवे परिसर और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ, हरित और यात्री-अनुकूल बनाने में सामूहिक ज़िम्मेदारी के महत्व को पुष्ट किया। ऐसी पहलों के साथ, सोलापुर मंडल 'स्वच्छ रेल - स्वच्छ भारत' के विज़न के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता रहा है, और सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सुखद यात्रा सुनिश्चित करता है।

घाटकोपर जेसीबी मौत मामले में आरोपी गिरफ्तार

मुंबई। घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति की जेसीबी से कुचलकर मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया था। हालांकि, आज उसने खुद ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कुर्ला पुलिस ने उसे आज अदालत में पेश किया और दुर्घटना में शामिल जेसीबी को जब्त कर लिया गया है, कुर्ला रेलवे स्टेशन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संभाजी यादव ने बताया। इस बीच, आरोपी का नाम भरत रामदास यादव है। घाटकोपर पूर्व में पुरानी टिकट खिड़कियों को तोड़कर उस स्थान पर एक नया निर्माण करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए पुरानी इमारत के मलबे को हटाने का काम जारी है। इसके लिए इस्तेमाल की जा रही जेसीबी से एक अज्ञात व्यक्ति की कुचलकर मौत हो गई। उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन आरोपी जेसीबी चालक भरत रामदास यादव इस घटना के बाद फरार हो गया था। रेलवे

भरत रामदास यादव
ACR No - 884/2025 कलम 106(1) BNS

पुलिस उसे ढूंढती हुई भांडुप स्थित उसके घर गई। हालाँकि, आरोपी अपनी पत्नी के साथ भाग गया था। अब पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया है। यह दुर्घटना 17 सितंबर (बुधवार) की आधी रात के आसपास हुई। इस जगह पर पुराने निर्माण को तोड़ने और उसके मलबे को हटाने और अन्य तोड़फोड़ का काम चल रहा है। इसके लिए जेसीबी क्रमांक MH 02 - E UV - 6747 का इस्तेमाल किया जा रहा है, और भरत रामदास यादव चालक के रूप में काम कर रहा था। जब वह रात में जेसीबी को दूसरी जगह ले जा रहा था, तब रात 12 बजे मृतक अज्ञात व्यक्ति जेसीबी के नीचे कुचला गया। हालांकि, जैसे ही चालक को इसका एहसास हुआ, चालक भरत यादव जेसीबी के साथ घटनास्थल से फरार हो गया। इस बीच, पुलिस ने जेसीबी के नीचे कुचले गए अज्ञात व्यक्ति को रात 1 बजे राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया था। हालांकि, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसलिए, पुलिस ने आरोपी भरत रामदास यादव के खिलाफ काम में लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था।इस मामले की जांच पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत चौधरी द्वारा किया जा रहा है

'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत ईटीसी केंद्र में विशेष बच्चों की दंत जाँच

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

एनएमयू ईटीसी केंद्र में विभिन्न आयु वर्ग के मानसिक रूप से मंद, मूक-बधिर, ऑटिस्टिक, दृष्टिबाधित, अधिगम अक्षमता और बहु-दिव्यांग बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और सेवा सुविधाओं का लाभ मिलता है। शिक्षा और चिकित्सा के साथ-साथ, ईटीसी केंद्र के माध्यम से इन विशेष बच्चों के लिए कई अन्य गतिविधियाँ भी संचालित की जाती हैं।

केंद्र सरकार के 'स्वच्छ भारत मिशन', 'स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025' के अंतर्गत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान चला रहा है।

तदनुसार, मनपा आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के मार्गदर्शन में, 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत, 17 सितंबर 2025 को, नवी मुंबई मनपा ईटीसी केंद्र और डॉ. जीडी पोल फाउंडेशन के वाई.एम.टी. डेंटल कॉलेज, खारघर द्वारा संयुक्त रूप से स्नेह संस्था के माध्यम से परियोजना का आयोजन किया गया। ईटीसी केंद्र में दिव्यांग बच्चों के लिए एक दंत जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दंत जांच शिविर में विभिन्न विकलांगता श्रेणियों जैसे बधिर, मानसिक रूप से मंद, बहुदिव्यांग और दृष्टिहीन कुल 210 विशेष बच्चों ने लाभ उठाया।

इस शिविर का शुभारंभ साक्षी आमले और वरद भाटे ने डॉक्टरों के मार्गदर्शन में किया। इस समय, रेणु तायवाड़े के साथ चिकित्सा दल ने विशेष बच्चों की दंत जांच की और आवश्यकतानुसार उन्हें आगे के उपचार के लिए मार्गदर्शन दिया।

उक्त दंत जांच शिविर का आयोजन केंद्र की संचालिका डॉ. अनुराधा बाबर ने अपने सहयोगियों के साथ आयुक्त के मार्गदर्शन में किया। कैलाश शिंदे और अपर आयुक्त श्री सुनील पवार के नियंत्रण में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कार्यालय अधीक्षक के साथ-साथ मानसिक मंदित विभाग और बधिर एवं श्रवण बाधित विभाग के शैक्षिक प्रबंधकों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया।

कृष्णा कदम को 'अटल भूषण पुरस्कार 2025' घोषित

चिकित्सकीय सामाजिक कार्य की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। अटल फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय अटल अवॉर्ड 2025 तथा अटल भूषण पुरस्कार 2025 समारोह आज 19 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुंबई के कदम कृष्णा मेडिकल सहायता कक्ष के संस्थापक कृष्णा कदम को 'अटल भूषण पुरस्कार' प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह जानकारी अटल फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा अपर्णा सिंह ने दी।

कृष्णा कदम ने वर्ष 2019 में कदम कृष्णा मेडिकल सहायता कक्ष की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को तुरंत शहरों में चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराना था। उन्होंने व्हॉट्सऐप ग्रुप के माध्यम से हजारों सदस्य, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, साथ ही सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा। इस नेटवर्क के जरिए ज़रूरतमंद मरीजों तक समय पर मदद पहुंचाई जाती है।

उनके इस अभियान से दिव्यांग, मूक-बधिर और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को भी नियमित मदद मिलती रहती है। समाज के हर वर्ग के ज़रूरतमंदों के लिए निरंतर काम कर रहे कृष्णा कदम के चिकित्सकीय-सामाजिक योगदान की सराहना अब तक कई संस्थाओं द्वारा की जा चुकी है।

'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य जाँच अभियान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

शहर की सफाई के लिए प्रतिदिन सुबह जल्दी काम शुरू करने वाले सफाई कर्मचारियों के समर्पित कार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल हेतु 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत नगर निगम मुख्यालय स्थित ज्ञान केंद्र में एक विशेष स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का 500 से अधिक सफाई कर्मचारियों और कर्मचारियों ने लाभ उठाया।

स्वच्छता भारत मिशन के निर्देशानुसार, 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में स्वच्छता संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान का क्रियान्वयन मनपा आयुक्त डॉ. कैलाश

शिंदे के मार्गदर्शन में प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत, 'स्वच्छता मित्र सुरक्षा शिविर' का आयोजन किया गया और वहाँ सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसमें मनपा मुख्यालय के कुछ कर्मचारियों ने भी स्वास्थ्य जाँच कराई। इस जाँच में रक्त परीक्षण, रक्तचाप, मधुमेह, सीबीसी, आँख, नाक, कान, गला, दाँत और आहार संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। शल्य चिकित्सकों, चिकित्सकों और अन्य विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न परीक्षण भी किए गए और आवश्यकतानुसार आगे के उपचार की सलाह दी गई तथा नगर निगम अस्पताल में और उन्नत परीक्षण किए गए। इसी प्रकार, यहाँ आयोजित रक्तदान शिविर को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 30 कर्मचारियों ने राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में स्वेच्छा से रक्तदान किया। अपर आयुक्त सुनील पवार, प्रशासन विभाग के उपायुक्त किसनराव पलांडे, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत जावड़े, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के उपायुक्त डॉ. अजय गाडे, आपातकालीन विभाग की उपायुक्त ललिता बाबर, कार्यकारी अभियंता प्रवीण गाडे और अन्य गणमान्य लोगों ने शिविर स्थल का दौरा किया और निरीक्षण प्रक्रिया का निरीक्षण किया।

पश्चिम रेलवे

विद्युत (विद्युत) कार्य

वरिष्ठ डीईई/पी/मुंबई सेंट्रल, मुंबई ई-निविदा संख्याः EL-81-7-926-WA-44 दिनांक 17-09-2025 आमंत्रित करता है। **कार्य और स्थानः मुंबई सेंट्रलः-** मुंबई सेंट्रल मुख्य स्टेशन पर सीओपी और दिव्यांगजन सुविधा के जंग लगे संरचनात्मक स्टील के सुधार के संबंध में विद्युत (विद्युत) कार्य। **कार्य की अनुमानित लागतः** 36,92,886/- **ब्याज राशिः** 73,900/- **जमा करने की तिथि और समयः** 13.10.2025, 15:00 बजे तक। **खोलने की तिथि और समयः** 13.10.2025 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएँ। 0611

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

दूरसंचार सुविधा में सुधार

वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता (सीओ), द्वितीय तल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400 008, ई-निविदा संख्याः WR-MMCT-SnT-STTD-22-2025 दिनांक 04/09/2025 आमंत्रित करता है। **कार्य का नामः** चर्चगेट-विरार उपनगरीय खंड की कोडल लाइफ के आधार पर दूरसंचार सुविधा में सुधार एवं विस्तार तथा दूरसंचार परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन। **कार्य की लागतः** 9,10,92,649.51/- **बोली सुरक्षाः** 6,05,500/- **ई-निविदा दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः** 03.10.2025, 15:00 बजे तक। **ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समयः** 03.10.2025 को 15:30 बजे।निविदा वेबसाइट www.ireps. gov.in पर देखी जा सकती है। 0610

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

मौजूदा दूरसंचार नेटवर्क का उन्नयन

वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता (सीओ), द्वितीय तल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400008, ई-निविदा संख्याः WR-MMCT-SnT-STTD-014-2025 दिनांक 17/09/2025 आमंत्रित करता है। **कार्य का नामः चर्चगेटः** मौजूदा दूरसंचार नेटवर्क का उन्नयन और महाप्रबंधक कार्यालय भवन एवं चर्चगेट स्टेशन भवन में स्थापित पुराने/पुराने दूरसंचार उपकरणों एवं तारों को बदलना। **कार्य की लागतः** 9,71,05,813.95/- **बोली सुरक्षाः** 6,35,500/- **ई-निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः** 09.10.2025, 15:00 बजे तक। **ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समयः** 09.10.2025 को 15:30 बजे। निविदा वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 0609

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

रविवार को मध्य रेल के मुंबई मंडल पर मेगा ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल, मुंबई मंडल दिनांक 21.09.2025 को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए अपने उपनगरीय खंडों पर निम्नानुसार मेगा ब्लॉक परिचालित करेगाः

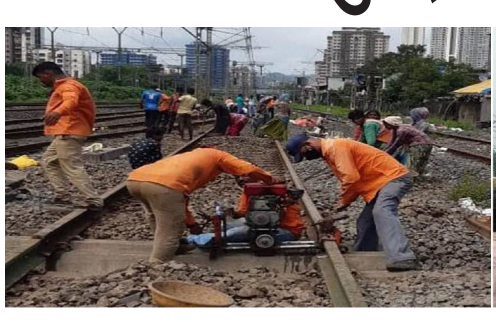

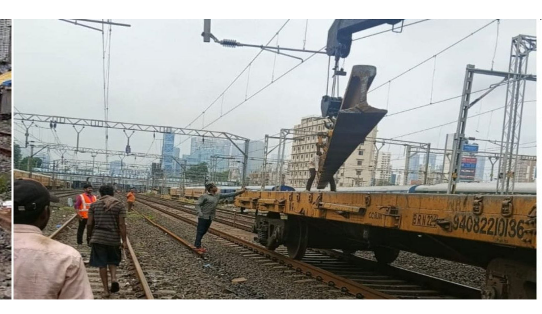

ठाणे और कल्याण स्टेशनों के बीच सुबह 10.40 बजे से दोपहर 15.40 बजे तक अप और डाउन फास्ट लाइन।

09.34 बजे से दोपहर 15.03 बजे तक सीएसएमटी मुंबई से प्रस्थान करने वाली डाउन फास्ट/सेमी-फास्ट लोकल सेवाओं को ठाणे और कल्याण स्टेशनों के बीच डाउन स्लो लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा और वे अपने संबंधित निर्धारित ठहरावों के अलावा कलवा, मुंब्रा और दिवा स्टेशनों पर रुकेंगी और अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुँचेंगी। सुबह 10.28 बजे से दोपहर 15.40 बजे तक कल्याण से प्रस्थान वाली अप फास्ट/सेमी-फास्ट सेवाओं को कल्याण और ठाणे स्टेशनों के बीच अप स्लो लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा। ये सेवाएं अपने निर्धारित ठहरावों के अलावा दिवा, मुंब्रा और कलवा स्टेशनों पर रुकेंगी। इसके बाद, मुलुंड स्टेशन पर अप फास्ट लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी और अपने निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से गंतव्य पर पहुँचेंगी। सीएसएमटी/दादर से छूटने वाली डाउन मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को ठाणे और कल्याण स्टेशनों के बीच पाँचवीं लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा। सीएसएमटी/दादर पहुँचने वाली अप मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को कल्याण और ठाणे/विक्रोली स्टेशनों के बीच छठी लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा। पनवेल और वाशी स्टेशनों के बीच अप और डाउन हार्बर लाइनें (पोर्ट लाइन को छोड़कर) सुबह 11.05 बजे से शाम 16.05 बजे तक।पनवेल से सुबह 10.33 बजे से दोपहर 15.49 बजे तक सीएसएमटी की ओर जाने वाली अप हार्बर लाइन सेवाएँ तथा सीएसएमटी से सुबह 9.45 बजे से दोपहर 15.12 बजे तक बेलापुर/पनवेल की ओर जाने वाली डाउन हार्बर लाइन सेवाएँ रद्द रहेंगी। पनवेल से सुबह 11.02 बजे से दोपहर 15.53 बजे तक ठाणे की ओर जाने वाली अप ट्रांस-हार्बर लाइन सेवाएँ तथा ठाणे से सुबह 10.01 बजे से दोपहर 15.20 बजे तक पनवेल की ओर जाने वाली डाउन ट्रांस-हार्बर लाइन सेवाएँ रद्द रहेंगी। ब्लॉक अवधि के दौरान सीएसएमटी मुंबई-वाशी सेक्शन पर विशेष लोकल ट्रेनें चलाई जाएँगी। ब्लॉक अवधि के दौरान ठाणे-वाशी/नेरुल स्टेशनों के बीच ट्रांस-हार्बर लाइन सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी। ब्लॉक अवधि के दौरान पोर्ट लाइन सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी। ये रखरखाव मेगा ब्लॉक बुनियादी ढाँचे के रखरखाव और संरक्षा के लिए आवश्यक हैं। यात्रियों से आग्रह है कि वे इससे होने वाली असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन को सहयोग करें।

मुंबई से 4 करोड़ रुपये के आभूषण और नकदी लेकर फरार होने के आरोप में तीन गिरफ्तार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत परेल इलाके में एक ज्वैलरी से 4 करोड़ 7 लाख 38 हजार रुपये के सोने के आभूषण और नकदी लेकर राजस्थान फरार होने वाले मुख्य आरोपी और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके नाम जीतू नवाराम चौधरी, भरत कुमार ओटाराम चौधरी और कमलेश वाघाराम चौधरी हैं। पुलिस उपायुक्त परिमंडल 4 आर रागसुधा के मार्गदर्शन में, भोईवाड़ा पुलिस ने 4 करोड़ 7 लाख 38 हजार का लगभग 70 प्रतिशत जब्त कर लिया है। 8 और 9 सितंबर के बीच, परेल में वर्धमान कृपा बिल्डिंग, डॉ बी ए रोड, जलीचंद ज्वेलर्स शॉप में काम करने वाले एक कर्मचारी जीतू नवाराम चौधरी ने ज्वेलरी से आभूषण चुरा लिए थे और भाग गया था। शिकायतकर्ता की शिकायत पर भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।पुलिस उपायुक्त आर. रागसुधा के मार्गदर्शन में भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन की एक टीम आरोपी के गाँव सादडा, ताल. बाली, जिला. पाली, राजस्थान राज्य भेजी गई। इस दौरान, अपराध जांच शाखा, सेल 4 की एक टीम भी समानांतर रूप से अपराध की जांच कर रही थी। पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर और गुप्त मुखबिरों की मदद से आरोपी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके अन्य 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे अब तक अपराध में शामिल 70 प्रतिशत संपत्ति जब्त कर ली गई है। आरोपी जीतू नवाराम चौधरी, कमलेश वाघाराम चौधरी और भरत कुमार ओटाराम चौधरी एक ही तालुका में रहते हैं। भोईवाड़ा पुलिस ने राजस्थान पुलिस की मदद से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और आगे की जांच की जा रही है।

कुंभ मेले के मद्देनजर शिरडी हवाई अड्डे पर विमान पार्किंग की सुविधा बढ़ाएँ- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। नासिक और उसके आसपास के क्षेत्रों में आगामी कुंभ मेले के मद्देनजर, शिरडी हवाई अड्डे का शेष कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हवाई अड्डे पर विमान पार्किंग की सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए।

महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी (एमएडीसी) के निदेशक मंडल की 92वीं बैठक मुख्यमंत्री श्री फडणवीस की अध्यक्षता में सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (विमान संचालन) संजय सेठी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी की उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक स्वाति पांडे, सिडको के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विजय सिंघल, मुख्यमंत्री के निवेश सलाहकार कौस्तुभ धावसे आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि

शिरडी में विमानों की पार्किंग दरें अन्य हवाई अड्डों की तुलना में कम रखी जानी चाहिए। शिरडी के महत्व और आने वाले दिनों में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, हवाई अड्डे के पास एक पाँच सितारा होटल की सुविधा होना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए जगह सुनिश्चित की जानी चाहिए और यहाँ प्रतिष्ठित होटल कंपनियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। यवतमाल में हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई बढ़ाने की आवश्यकता बताते हुए, उन्होंने इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उन जगहों पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए जहाँ निजी कंपनियाँ हवाई अड्डे का संचालन अपने हाथ में लेती हैं, लेकिन बीच में ही बंद हो जाती हैं।

एमएडीसी की उपाध्यक्ष श्रीमती पांडे ने राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों के चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। शिरडी में रनवे और टैक्सीवे के पुनर्निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ब्लॉक का काम पूरा हो चुका है और इसे भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अक्टूबर 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए यात्री टर्मिनल भवन का काम चल रहा है। इस संबंध में विस्तृत वास्तुशिल्प योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और उन्हें अनुमोदन के लिए विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नागपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की परियोजना नवंबर तक पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने अमरावती (बेलोरा), पुरंदर, कराड, गढ़चिरौली, रत्नागिरी आदि हवाई अड्डों के विकास और विस्तार की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी।

पैन कार्ड क्लब निवेशक जमा राशि की समीक्षा गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने की

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। पैन कार्ड क्लब लिमिटेड में निवेशकों ने पैसा लगाया है। गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने इससे पहले 11 जून 2025 तक इन निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने की चल रही प्रक्रिया की समीक्षा की थी। तदनुसार, गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने आज मंत्रालय में एक और समीक्षा बैठक की।

महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय संस्थानों में) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत वित्तीय संस्थान पैन कार्ड क्लब लिमिटेड द्वारा की गई लगभग 7,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई।

पैन कार्ड क्लब लिमिटेड से प्रभावित निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलना चाहिए, इसलिए संबंधित एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अदालत का फैसला आने तक इस मामले में संरक्षित संपत्तियों में कोई अवैध लेनदेन न हो। साथ ही, यह जानकारी भी एकत्रित की जाए कि कितनी संपत्तियाँ संरक्षित हैं और कितनी संपत्तियाँ अभी तक संरक्षित नहीं हैं। इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री कदम ने कहा कि सक्षम प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाही शीघ्र पूरी करने के लिए सभी संबंधित जिला कलेक्टरों के साथ एक बैठक भी की जाएगी।

राज्य मंत्री श्री कदम ने कहा कि पैन कार्ड क्लब लिमिटेड सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी कानूनी प्रक्रियाएँ शीघ्र पूरी करे ताकि प्रभावित निवेशकों को उनका पैसा मिल सके और निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द वापस दिलाने की कार्रवाई की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव (गृह) अनूप कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक दीपक देवराज, उप सचिव यमुना जाधव सहित सेबी के वरिष्ठ अधिकारी, जाँच अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और निवेशक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश

नवी मुंबई नगर निगम में शामिल 14 गाँवों में जलापूर्ति, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएँ और स्कूल निर्माण कार्यों को तत्काल प्राथमिकता दी जाए

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई नगर निगम में शामिल 14 गाँवों में जलापूर्ति, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएँ और स्कूल निर्माण कार्यों को तत्काल प्राथमिकता दी जाए। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई नगर आयुक्त को इस क्षेत्र में विभाग हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।

नवी मुंबई नगर निगम सीमा में शामिल 14 गाँवों की विभिन्न मांगों को लेकर सह्याद्री अतिथि गृह में एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे बोल रहे थे। इस अवसर पर सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, विधायक राजेश मोरे, उपमुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव गोविंदराज, नवी मुंबई नगर आयुक्त कैलाश शिंदे, ठाणे जिला कलेक्टर श्रीकृष्ण पांचाल आदि उपस्थित थे।

नवी मुंबई नगर निगम को इन गाँवों में मूलभूत सुविधाएँ शीघ्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। अस्थायी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पोर्टा केबिन की मदद से क्लीनिक शुरू किए जाएं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नावली स्थित पुराने भवन में नया अस्पताल शुरू करने के लिए संबंधितों को निर्देश दिए जाएं।

वकलां स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए और नवी मुंबई मनपा के सफाई कर्मचारियों द्वारा इन गांवों में सफाई की जाए। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण तुरंत हटाए जाएं और इन गांवों के सरकारी कार्यालयों को नवी मुंबई में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे ने निर्देश दिए।

इन गांवों के लिए योजना तैयार करने का काम चल रहा है और ड्रोन के जरिए सड़कों, बुनियादी ढांचे, भूमि उपयोग आदि का सर्वेक्षण किया जा रहा है, ऐसा आयुक्त श्री शिंदे ने बताया। नवी मुंबई मनपा के 2025-26 के बजट में इन 14 गांवों के लिए 19 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, जलापूर्ति, सीवेज, फुटपाथ, सड़क जैसी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर शामिल हैं, ऐसा आयुक्त ने बताया।

क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन

कौशल विकास से ही देश का विकास संभव - मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। कौशल विकास देश की प्रगति की कुंजी है। कौशल विकास में, न केवल योजनाओं का नियोजन, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय कौशल विकास की सफलता की कहानियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संचार, समन्वय और एकीकरण भी समय की आवश्यकता है। कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि राज्य आपस में और केंद्र सरकार के बीच बेहतर संवाद बनाए रखते हुए 'टीम इंडिया' के रूप में काम करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करें।

केंद्रीय कौशल विकास विभाग और राज्य कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग द्वारा सह्याद्री अतिथि गृह में 'क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यशाला' का आयोजन किया गया। कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा इस कार्यशाला

के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय कौशल विकास विभाग की सचिव देबाश्री मुखर्जी, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की कार्यकारी सदस्य डॉ. विनीता अग्रवाल, निदेशक गुंजन चौधरी, महाराष्ट्र राज्य कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवप्रवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, आयुक्त लहुराज माली, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय की निदेशक माधवी सरदेशमुख, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. अपूर्व पालकर सहित महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के कौशल विकास विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मंत्री लोढ़ा ने कहा कि क्षमता निर्माण जितना ही महत्वपूर्ण है 'समन्वय'। केवल क्षमता बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका उपयोग कहाँ करना है, यह जानने के लिए उचित समन्वय आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर हर तीन महीने में और राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष में एक बार सभी कौशल विकास विभागों की बैठक अनिवार्य है।

मंत्री लोढ़ा ने कहा कि मेहनती लोगों का सम्मान ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में हुनर ??होना बहुत अच्छी बात है। इसलिए, किसी हुनरमंद व्यक्ति का सम्मान उसके काम के बजाय उसके हुनर ??को देखकर किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में उच्च शिक्षित युवाओं की संख्या बड़ी है और साथ ही कई कंपनियों में हज़ारों पद खाली हैं। लेकिन दोनों का मिलान करने की व्यवस्था कम है। इसके लिए 'जॉब मैचिंग ब्यूरो' शुरू करना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना करके इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि यह एक दिन की कार्यशाला नहीं, बल्कि देश भर में कौशल विकास करने वाले नेताओं का एक नेटवर्क बनाने का माध्यम होना चाहिए।

बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नवीन बहुविषयक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक प्रयोगों, स्वदेशी तकनीक के उपयोग और नवीन बहुविषयक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है। यदि शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान का समन्वय किया जाए, तो बांस उद्योग क्षेत्र का तेजी से विकास होगा और बांस उद्योग रोजगार और पर्यावरण विकास के अवसर पैदा करेगा, यह बात अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस के अवसर पर यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान (मित्रा) और फीनिक्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित बांस सम्मेलन के दूसरे दिन विशेषज्ञों ने कही।

बांस की खेती पर कम से कम चार वर्षों के प्रयोग, उपयुक्त किस्मों का चयन और विभिन्न व्यास के अनुसार उपयोग महत्वपूर्ण हैं और उत्पादन के लिए छोटे केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है। बांस से संबंधित कार्य केवल सिद्धांत पर आधारित न होकर व्यावहारिक प्रयोगों पर आधारित होने चाहिए। बांस का उपयोग स्वास्थ्य, ऊर्जा, संरचना, कृषि और उत्पाद जैसे प्रमुख क्षेत्रों में किया जा सकता है।

बांस की खेती से न केवल वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, बल्कि अगले 5 से 10 वर्षों में लोगों के लिए आय का एक स्रोत भी तैयार होगा। 'आईआईटी' गुवाहाटी ने हाल ही में सेना के सहयोग से बांस से बंकर बनाए हैं और ये विकल्प कंक्रीट और लकड़ी की बजाय लागत-प्रभावी और उपयोगी साबित हो रहे हैं। इसके लिए विश्वविद्यालयों को नर्सरी प्रबंधन, बांस मिश्रित प्रौद्योगिकी, ऊर्जा क्षेत्र के पाठ्यक्रमों के साथ-साथ बांस विज्ञान में एम.टेक. जैसे उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने और प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, यदि स्वदेशी डिजाइनों और उपकरणों पर जोर दिया जाए, तो देश में हजारों करोड़ रुपये का बांस उद्योग स्थापित किया जा सकता है, जिसके लिए उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों और समाज के बीच आपसी सहयोग आवश्यक है, संगोष्ठी में उपस्थित गणमान्यों ने कहा।

बांस के पर्यावरण-अनुकूल और बहुउद्देशीय महत्व को ध्यान में रखते हुए, उन्हें प्राथमिक स्तर से ही स्कूली छात्रों को बांस की खेती, संरक्षण और इसके विभिन्न उपयोगों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। इस सम्मेलन की संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने भी विश्वास व्यक्त किया कि स्कूली पाठ्यक्रम में बांस परियोजनाओं, प्रदर्शनों और शैक्षिक गतिविधियों को शामिल करने से पर्यावरण के प्रति जागरूक पीढ़ी के निर्माण में मदद मिलेगी।

इस सेमिनार में डॉ. अजय ठाकुर, आनुवंशिकी और वृक्ष सुधार विभाग के प्रमुख, वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई), देहरादून, प्रोफेसर और ग्रामीण विकास और योजना विभाग के प्रमुख, नागालैंड विश्वविद्यालय, दीमापुर, डॉ. जयंत चौधरी, प्रोफेसर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के प्रमुख, डॉ. सुप्रतीक गुप्ता, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के प्रोफेसर, डॉ. निर्मला चोंगथम, वन आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, केरल वन अनुसंधान संस्थान (केएफआरआई), डॉ. ई. एम. मुरलीधरन, बांस और बेंत विकास संस्थान, अगरतला, त्रिपुरा के प्रमुख, डॉ. अभिनव कांत, सीईपीटी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद के प्रोफेसर, प्रो. आर. संकल्प, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन के प्रोफेसर और निदेशक, मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर, डॉ. मधुरा यादव, प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी गुवाहाटी, डॉ. पूनम कुमारी, वैज्ञानिक, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), डॉ. किशोर कुलकर्णी, प्रमुख, बांस विकास केंद्र, आईपीआरआईटीआई, बेंगलुरु, डॉ. विपिन चावला, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्थान रासायनिक प्रौद्योगिकी (आईसीटी), मुंबई के निदेशक डॉ. पराग आर. नेमाडे, एमआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, पुणे के निदेशक डॉ. नचिकेत ठाकुर और प्रो. चारुचंद्र कोर्डे ने भाग लिया। राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पर्यावरण सतत विकास कार्य बल के कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और उनका परिचय कराया।

जोगेश्वरी (एटी) पर 'स्वच्छता ही सेवा अभियान-2025' के अंतर्गत श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा 'स्वच्छता ही सेवा अभियान-2025' के अंतर्गत जोगेश्वरी (एटी) पर सफलतापूर्वक एक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल को मंडल रेल प्रबंधक पंकज सिंह तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक (ॅंश) सहित वरिष्ठ अधिकारियों का सक्रिय समर्थन एवं सहयोग प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली, जो एकता एवं स्वच्छता के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज सिंह, अनेक वरिष्ठ रेल अधिकारी एवं कर्मचारी, साथ ही नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के सदस्य इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हुए। सामूहिक सहभागिता और समन्वय का यह अनूठा उदाहरण स्वच्छता के प्रति पश्चिम रेलवे की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इस अवसर पर पंकज सिंह ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और उन्हें स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने दीर्घकालिक स्थायित्व हेतु स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों को अपनाने तथा समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। रेलवे कर्मचारियों एवं एनडीआरएफ टीम की सक्रिय और उत्साही भागीदारी ने इस अभियान को सफल एवं सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस पहल ने एक बार फिर पश्चिम रेलवे की स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से पश्चिम रेलवे न केवल पर्यावरणीय उत्तरदायित्व निभा रहा है, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में भी सक्रिय योगदान दे रहा है।

करण जौहर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, बिना परमिशन तस्वीर या आवाज के इस्तेमाल पर लगी रोक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और फिल्म निर्माता करण जौहर को उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में राहत प्रदान की है। न्यायालय ने आदेश दिया कि उनके विरुद्ध बनाए गए विवादास्पद वीडियो, मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाएँ। आदेश में ऐसी सभी 'अपमानजनक सामग्री' को तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया है। लाइव लॉ के अनुसार, न्यायालय ने कहा, 'प्रथम दृष्टया मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 7, 14 और 15 के प्लेटफार्मों पर उपलब्ध वीडियो, मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट में अपमानजनक और अपवित्र शब्दों के साथ-साथ ऐसे संकेत भी हैं जो आपत्तिजनक प्रतीत होते हैं। उक्त सामग्री वादी की प्रतिष्ठा और साख को धूमिल

करती है, जिससे उसकी ब्रांड वैल्यू प्रभावित होती है। वादी प्रथम दृष्टया ऐसे नकारात्मक उपयोग के विरुद्ध अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है।

फिल्म निर्माता की आपत्ति को देखते हुए, अदालत ने आगे कहा कि मुकदमे में जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स का ज़िक्र किया गया है, उन्हें हटाया जाना चाहिए क्योंकि वे बिना अनुमति के जौहर के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। अदालत ने आगे कहा, वादी का यह तर्क कि उक्त अकाउंट्स जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह कर सकते हैं कि ये अकाउंट्स वादी के आधिकारिक और/या अधिकृत अकाउंट हैं, प्रथम दृष्टया विश्वसनीय है।

रविवार को कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं

मुंबई। रेलपथ, सिगनलिंग तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा वसई रोड एवं विरार स्टेशनों के बीच शनिवार/रविवार अर्थात 20/21 सितम्बर, 2025 की मध्यरात्रि के दौरान अप एवं डाउन धीमी लाइनों पर 00.15 बजे से 04.15 बजे तक चार घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ब्लॉक अवधि के दौरान धीमी लाइनों की सभी उपनगरीय ट्रेनों को वसई रोड एवं विरार स्टेशनों के बीच फास्ट लाइनों पर चलाया जाएगा। ब्लॉक के दौरान कुछ उपनगरीय ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है। इसलिए, पश्चिम रेलवे उपनगरीय खंड पर रविवार, 21 सितम्बर, 2025 को कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।

'क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यशाला' में विशेषज्ञों ने कहा, कुशल जनशक्ति निर्माण के लिए क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। देश में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। उन्हें उचित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके, उन्हें रोज़गारोन्मुख बनाकर और उद्योगों को कुशल जनशक्ति प्रदान करके, देश कौशल की राजधानी बन सकता है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद इसके लिए कार्यरत है। केंद्रीय कौशल विकास विभाग और राज्य कौशल, रोज़गार, उद्यमिता एवं नवप्रवर्तन विभाग द्वारा सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में आयोजित 'क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यशाला' में मार्गदर्शक विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए कि कुशल जनशक्ति निर्माण के लिए क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की निदेशक कर्नल गुंजन चौधरी, एनडीए के वरिष्ठ प्रबंधक प्रकाश पांडे, केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के संयुक्त निदेशक नवीन कुमार और उप निदेशक श्री जिग्नेश ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर, नीना पाहुजा ने कहा कि कौशल क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का स्थान महत्वपूर्ण है और इसमें प्रशिक्षण भविष्य के लिए उपयोगी है। कर्नल चौधरी ने कौशल विकास केंद्र शुरू करने और चलाने की जानकारी दी।

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संगठन के कार्यों की समीक्षा

मुंबई। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश अबितकर ने महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (एमएसएसीएस) के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में राज्य भर में एचआईवी की रोकथाम, उपचार और जागरूकता गतिविधियों पर एक प्रस्तुति दी गई। बैठक में राज्य में एचआईवी की वर्तमान स्थिति पर गहन विचार किया गया। उपचार के तौर-तरीकों, जागरूकता अभियानों और कमजोर समुदायों तक प्रभावी सेवा वितरण पर विस्तार से चर्चा की गई। महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा क्रियान्वित योजनाओं को आने वाले समय में और अधिक प्रभावी और कुशलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाना चाहिए। साथ ही, लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री अबितकर ने एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यरत तंत्रों की दक्षता बढ़ाने, विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित करने और जनता में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

सम्पादकीय

पंजाब में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ घृणा अभियान जोरों पर

पंजाब में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों का उड़ाया जाने वाला उपहास अब उनके विरोध यहां तक कि उन्हें पंजाब से बाहर करने की मांग तक पहुंच गया है। इन मजदूरों से खैनी-गुटका खाने से लेकर हर छोटे-मोटे अपराधों से इनका नाम जोड़ कर और बाहरी राज्यों से आए अपराधी किस्म के लोगों द्वारा किए गए घिनौने कृत्यों की आड़ में प्रदेश में घृणा अभियान चलाया जा रहा है।

गत दिनों 13 सितम्बर को होशियारपुर में दूसरे राज्य से आए एक व्यक्ति ने 5 वर्षीय हरवीर के साथ दानवों जैसा व्यवहार किया और बाद में उसकी नृशंस हत्या कर दी। पुलिस ने इसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है परन्तु इस घटना से उपजे आक्रोश की आड़ में कट्टरपंथी शक्तियों ने अपना घिनौना खेल खेलना शुरू कर दिया है। अब राज्य में कई स्थानों पर पंचायतें दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर रही हैं। केवल होशियारपुर में ही 25 पंचायतें इस तरह का प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं जिसमें बाहर से आए श्रमिकों को काम न देने, रहने को मकान न देने, उनके आधार कार्ड व राशन कार्ड न बना कर देने की बात कही गई है। बठिंडा में भी गहरी देवी नगर की पंचायत ने इस तरह का प्रस्ताव पारित किया है।

पंजाब में इन दिनों सोशल मीडिया पर बाहरी राज्यों से आए इन मजदूरों के खिलाफ घृणा अभियान चलाया जा रहा है, जिनमें मेहनती मजदूरों की छवि को अपराधिक बना कर पेश किया जा रहा है। इन मजदूरों के खिलाफ विषवमन करने वालों में कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में बैठे अलगाववादी लोग सबसे आगे हैं। इसी के चलते पंजाब में प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी मजदूरों को गाँवों में काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने विधानसभा चुनाव प्रचार अभिचान में उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले प्रवासी मजदूरों को अपमानजनक अर्थ में 'भैया' कहा था। दुखद बात यह है कि उस समय मंच पर मौजूद पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने चन्नी के इस शर्मनाक ब्यान पर तालियां बजाई थीं। ऐसा ही एक मामला आया है मोहाली से, जहाँ एक गाँव से प्रवासी मजदूरों को भगाया गया। मोहाली जिले के जंडपुर गाँव में प्रवासी मजदूरों को घर किराए पर लेने की अनुमति नहीं है। गाँव में उनके लिए 11 तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें रात 9 बजे के बाद बाहर जाने पर प्रतिबंध, धूम्रपान और तम्बाकू चबाने पर पाबंदी, और उनके कपड़ों को लेकर सख्त नियम शामिल हैं। गाँव के गुरुद्वारा कमेटी ने यह फैसला लिया कि प्रवासी मजदूर अब गाँवों में नहीं रह सकते। इसी साल अगस्त में मुंडो संगतियां गाँव से प्रवासी मजदूरों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। जब मजदूरों को काम से निकाल कर गाँव से बाहर कर दिया गया, तो यह मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तक पहुँचा। वैभव वत्स नामक एक व्यक्ति ने प्रवासी मजदूरों को अवैध रूप से निकालने के खिलाफ याचिका दायर की, जिससे यह मामला कानूनी चर्चा में आया। दूसरी तरफ, प्रवासी मजदूरों का दर्द है कि वे अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, लेकिन उन्हें यहां सम्मान नहीं मिलता। मजदूरों को भैया कहकर अपमानित किया जाता है और उनके सांवले रंग के कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लुधियाना, जालन्धर, अमृतसर जैसे उद्योगिक नगरों में अपराधी तत्व आटो चालकों, रेहड़ी-फड़ी वालों, फेरी वालों को अकेला देख कर लूट लेते हैं। वेतन वाले दिन यह श्रमिक इन अपराधी तत्वों का विशेष लक्ष्य होते हैं और फैक्ट्री से घर जाते समय इनको रास्ते में लूट लिया जाता है। पुलिस प्रशासन इनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देता और कई बार तो प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की जाती। बहुत सी श्रमिक बस्तियां सडक़, बिजली, पानी, सीवरेज जैसे मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं और इन श्रमिकों को नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। राजनीतिक दल बहला फुसला कर इनसे वोटें तो हासिल कर लेते हैं परंतु असंगठित होने के कारण इनकी मांगों पर गौर तक नहीं किया जाता। समय की मांग है कि आपराधिक कृत्यों पर सख्त कार्रवाई करते हुए श्रमिक वर्ग के खिलाफ अभियान चलाने वाली शक्तियों के खिलाफ सख्ती से पेश आया जाए और पंजाब में निवास कर रहे बाहरी राज्यों के श्रमिकों को पूरी सुरक्षा व नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।

राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर पॉश एक्ट, 2013 से प्राप्त वैधानिक छूट एक नैतिक विडंबना नहीं तो क्या?

राजनीतिक दलों को महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा संबंधी कानून प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट (पॉश एक्ट), 2013 से प्राप्त वैधानिक छूट किसी नैतिक विडंबना से कम नहीं है, चाहे इसका विधिक कारण कुछ भी हो! यह हमारी संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की नैतिक लापरवाही या खामोशी दोनों का नतीजा है? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह तर्क कि राजनीतिक दल और उनके सदस्यों के बीच पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध नहीं होता है, किसी के गले नहीं उतरता है। यह अनुभव की व्यवहारिक कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता है।

यह ठीक है कि उनके बीच पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं होता, लेकिन दफ्तर और कार्यसंस्कृति दोनों होती है। यहां तक कि टूर के दौरान ठहरने वक्त नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं का कमरा आसपास ही रखा जाता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इससे राजनीतिक दलों व उनके नेताओं को कार्यकर्ताओं के शोषण का अंतहीन अधिकार मिल जाता है! खासकर, जब केंद्र और विभिन्न राज्यों की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आदि दल किसी कॉरपोरेट शैली से संचालित होती हों, उनके जनसंपर्क यानी प्रचार-प्रसार व कार्यसंचालन का तरीका लगभग वही हो, जब निर्वाचित राजनेताओं के धन भी पांच वर्ष में ही दुगुने-तिगुने से ज्यादा बढ़ जाते हों, जब राजनेताओं व उनके करीबी संगठन के नेताओं पर महिलाओं के शारीरिक शोषण के अनेक आरोप लगते आए हों, वैसे परिदृश्य में सियासी दलों और सियासतदानों को प्राप्त विधिक छूट उनके गलत इरादों को लीगल प्रश्रय नहीं देना है तो क्या है, यक्ष प्रश्न है?

भारत के अधिकांश लोगों को पता है कि देश की कानून निर्मात्री संस्था 'संसद', विधानसभा मंडलों में बैठे राजनेतागण खुद को 'अभिजात्य प्राणी' समझते हैं और खुद के फंसने वाला कानून कभी नहीं बनाते। वहीं, अपना सियासी हित साधने के लिए प्रायः द्विअर्थी कानून बनाते हैं। वाकई एक ही प्रवृति के विषयों में अस्पष्ट कानूनों की वजह से ही देश अमेरिका की भांति वकीलों का स्वर्ग बन चुका है। कोई भी नेता दो जगह से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दो जगहों की मतदाता सूची में नाम निकल जाने पर जानबूझकर बखेड़ा खड़ा किया जाता है। भूमि-भवन-स्वर्ण निवेश सम्बन्धी चीजों, शिक्षा-स्वास्थ्य-कारोबार आदि में अस्पष्ट कानूनों की वजह से निवेशक मालामाल और उपभोक्ता फटेहाल रहते हैं, आदि।

सबसे बड़ी विडंबना तो यह कि निर्वाचित होते ही, अपराधी/

दुष्कर्मी भी 'माननीय' करार दिए जाते हैं। यह स्थिति प्रशासनिक अधिकारियों व न्यायपालिका के लिए भी शर्मनाक है। साथ ही भारतीय बुद्धिजीवियों, सफल पेशेवर समूहों, विश्वविद्यालयों की पवित्र सोच पर करारा तमाचा है। ऐसे में सुलगता हुआ सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट आरक्षण सम्बन्धी कानून और वक्फ बोर्ड कानून आदि में तो संशोधन करने का अधिकार रखता है, लेकिन नेताओं से जुड़े मामलों में उसकी बुद्धिमत्ता/प्रबुद्ध सोच को 'जंग' लग जाती है, सांप सूंघ जाता है जो वैधानिक 'सामाजिक टेटनस/ मानसिक विष' जैसे 'जानलेवा रोगों' की वजह बन जाते हैं।

स्वाभाविक सवाल है कि हमारे राजनेता जेल से चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं, अपनी सैलरी व भत्ता खुद ही बेहिसाब बढ़ा सकते हैं, राजनीतिक चंदा के लिए 'चोर दरवाजे' छोड़ सकते हैं, संसद के भीतर-बाहर कुछ भी अनाप-शनाप बोल सकते हैं, जिससे सामाजिक-राष्ट्रीय हितों पर चोट पहुंचती है, आदि। इनके कार्यकर्ता पाकिस्तान-बंगलादेश का झंडा लहरा सकते हैं, लेकिन इस पर कभी तर्कसंगत बहस नहीं होती! बेलगाम सोशल मीडिया इनका आधुनिक प्रचार हथियार बन चुका है। क्रिप्टो करेंसी इनके अवैध लेन-देन का साधन बन चुका है।लेकिन एक समान कानून की याद इन्हें कतई नहीं आती। इससे आम व्यवसायियों के कारोबारी हित भी प्रभावित होते हैं।

कोढ़ में खाज यह कि अब सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि 'राजनीतिक दलों में सदस्यता रोजगार जैसी नहीं है- इसमें न तो नियमित वेतन है और न ही संविदात्मक/नौकरी संबंधी अनुबंध।' सवाल है कि कार्यकर्ता दिन-रात पार्टी की सेवा में लगे रहते हैं या नहीं? इनको मानदेय क्यों नहीं दिया जाता? क्या इसी वजह से ये प्रशासनिक या सामाजिक 'दलाली' करते हैं और किसी तरह निर्वाचित नेताओं के लोकल एजेंट बनकर अपना गुजारा करते हैं। क्या इसी वजह से भ्रष्टाचार, शिष्टाचार नहीं बन गया है? यह कौन नहीं जानता कि अधिकारियों-जनप्रतिनिधियों/मंत्रियों के बीच दलाली करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ही नेटवर्क 'गर्म गोश्त' की भी दलाली करता है, इसलिए इन्हें भी पॉश एक्ट 2013 के दायरे में लाए जाने की जरूरत है। रहस्य न खुले, इसलिए इस धंधे में एक-दूसरे की जान लेना स्वाभाविक बात है! जिसे प्रशासनिक पहुंच के बल पर दबा दिया जाता है। बावजूद इसके कुछ मामले सुर्खियां बन जाते देखे-सुने जाते हैं।

बताया जाता है कि पॉश एक्ट की परिभाषा में वही संगठन आते हैं जहाँ 'रोजगार और भुगतान' के आधार पर कर्मचारी और नियोक्ता के संबंध मौजूद हैं। चूंकि राजनीतिक पार्टी में कोई महिला कार्यकर्ता बनने का अर्थ 'नौकरी' पाना नहीं है, बल्कि यह केवल 'मेम्बरशिप' का मामला है, जिसमें औपचारिक रोजगार संबंध स्पष्ट नहीं होता। ऐसे में राजनीतिक दलों के कार्य के दायरे (जैसे रैलियां, जनसंपर्क, अभियान आदि) को कानूनी तौर पर 'स्थायी कार्यालय या कार्यस्थल' की तरह चिन्हित नहीं किया जा सकता- यह अत्यंत गतिशील और अस्थिर होते हैं।

वहीं, चूंकि इस क़ानून के प्रभाव और विकल्प असरकारक हैं, इसलिए राजनीतिक दलों को मिला छूट इस कानून की सफलता पर संशय पैदा करता है। इस छूट के कारण यदि किसी महिला राजनीतिक कार्यकर्ता को उत्पीड़न का सामना करना पड़े तो वह पॉश एक्ट 2013 के तहत शिकायत नहीं कर सकती है। हालांकि वह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) या किसी अन्य आपराधिक कानून का उपयोग कर सकती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत किया है कि राजनीतिक दलों को पॉश एक्ट, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने की बाध्यता भी नहीं है। इसलिए स्वाभाविक सवाल है कि राजनीतिक दलों को यह छूट क्यों? क्या वही कानून बनाते-बनवाते हैं, सिर्फ इसलिए!

हालांकि, अन्य देशों में कुछ वैकल्पिक उपाय भी उपलब्ध हैं, जिसका भारत में अनुशरण किया जाना चाहिए। जैसे-कुछ देशों में राजनीतिक दल स्वेच्छा से महिलाओं के लिए आंतरिक आरक्षण या शिकायत व्यवस्था अपनाते हैं, किंतु भारत में कानूनी तौर पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वहीं, राजनीतिक दलों को कार्यस्थल महिला सुरक्षा कानूनों से छूट कोर्ट द्वारा इसलिए दी गई है क्योंकि वहां पारंपरिक वेतनभोगी रोजगार संबंध नहीं पाया जाता और उनकी कार्यप्रणाली 'स्थायी दफ्तर' जैसी नहीं होती। इसलिए स्वाभाविक सवाल यह है कि क्या यह एक बिडम्बनात्मक सोच व छूट नहीं है? इस पर देशव्यापी बहस खुद राजनीतिक महिला कार्यकर्ताओं के बीच ही करवायी जानी चाहिए।

बताते चलें कि पॉश एक्ट, 2013 ('कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और प्रतितोष अधिनियम') में 'नियोक्ता' और 'कर्मचारी' की परिभाषा स्पष्ट की गई है, जिसके तहत नियोक्ता की परिभाषा तय है। जैसा कि पॉश एक्ट की धारा 2(जी) में स्पष्ट किया हुआ है, 'नियोक्ता' वह व्यक्ति है जो किसी विभाग, संगठन, प्रतिष्ठान या कंपनी का प्रमुख हो या उसका प्रबंधन, पर्यवेक्षण या नियंत्रण करता हो। यानी संगठन का संचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति 'नियोक्ता' माना जाता है। जबकि 'कर्मचारी' की परिभाषा भी व्यापक है- इसमें नियमित, अस्थायी, संविदा, प्रशिक्षु, स्वैच्छिक या एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले सभी व्यक्ति आते हैं। वेतन, भत्ते या किसी अन्य प्रकार की पारिश्रमिक या बिना पारिश्रमिक के कार्यरत व्यक्ति भी 'कर्मचारी' की श्रेणी में आते हैं।

इस कानून की मुख्य बातें ये हैं कि 'नियोक्ता' और 'कर्मचारी' की परिभाषा संगठनात्मक संबंध और प्रबंधन के अधिकार से निर्धारित होती है न कि केवल वेतन या रोजगार अनुबंध से। वहीं, पॉश एक्ट, 2013 केवल उन्हीं संस्थाओं पर सीधे लागू होता है, जहाँ यह संबंध स्पष्ट रूप से मौजूद हो। इसप्रकार से पॉश एक्ट में 'नियोक्ता' संगठन के प्रमुख/प्रबंधक और 'कर्मचारी' उस संगठन में किसी भी रूप में (अस्थायी, स्थायी, संविदा आदि) कार्यरत व्यक्ति को कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं के हित संरक्षण से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून पर भी राजनीतिक असर पड़ा है, जिसके दुरुपयोग के बावजूद भारतीय संविधान एक मजबूत, जीवंत और अनुकूल दस्तावेज़ है, जो आज भी देश की लोकतांत्रिक, न्यायिक और नैतिक नींव का मुख्य आधार बना हुआ है। इसलिए उम्मीद है कि यहां व्याख्या की जा रही नजरिए से भी अविलंब कानूनी संशोधन किए, करवाये जाएंगे।

कहना न होगा कि संविधान सर्वोच्च कानून है, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण करता है और चेक-बैलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। इससे कोई भी व्यक्ति या संस्था विधि से ऊपर नहीं हो सकती, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप के समय भी नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा होती है। जहां तक राजनीतिक दुरुपयोग और संस्थागत सुरक्षा का सवाल है तो संविधान की कुछ धाराओं (जैसे- अनुच्छेद 356) का ऐतिहासिक रूप से दुरुपयोग हुआ है; परंतु सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई फैसले जैसे न्यायिक विराम ऐसे दुरुपयोग पर अंकुश लगाने में सफल रहे हैं, जिससे संविधान की संघीय संरचना सुरक्षित बनी रही है।

हाल के वर्षों में भी देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य संस्थाएं समय-समय पर संविधान के मूल उद्देश्यों की रक्षा के लिए सक्रिय रही हैं, भले ही राजनीतिक दल संविधान को अपने हित के हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। यह हमारे संविधान की अनुकूलनशीलता और लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो सराहनीय है। संविधान में लचीलापन है, जिससे समयानुसार जनता की आवश्यकताओं, सामाजिक संतुलन और नये अधिकारों को संशिधनों के द्वारा सम्मिलित किया जा सकता है। वहीं, संविधान राष्ट्रीय एकता, अल्पसंख्यक सुरक्षा और सामाजिक समावेशन की नींव तैयार करता है, जिससे राजनीतिक उठापटक के बावजूद देश की बुनियादी संरचना अखंड रहती है। इसलिए पॉश एक्ट 2013 के दायरे में राजनीतिक दलों और इस जैसे संगठनों को भी लाये जाने की माकूल कानूनी पहल की जानी चाहिए। इससे महिलाओं के प्रति सुनियोजित आपराधिक सोच में कमी आएगी।

जहां तक संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में तर्क का सवाल है तो संविधान व इसके संरक्षक विधि के शासन, अधिकारों की सुरक्षा, तंत्र की पारदर्शिता और कार्यकारी संरचना को संतुलन देते हैं। न्यायपालिकाएँ और संस्थाएं संवैधानिक व्याख्या कर राजनीतिक हस्तक्षेप पर नियंत्रण रखती हैं। इसके लचीलेपन के चलते समय के साथ संविधान अपनी प्रयोजनशीलता व प्रासंगिकता बनाए रखने में सफल है। अतः, राजनीतिक दवाबों और अस्थाई तौर पर गलत इस्तेमाल के बावजूद, भारतीय संविधान अपनी मूल भावना, संतुलन और स्थायित्व बनाए रखने में सक्षम है- यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति और भारतीय लोकतंत्र का संरक्षण है।

इसलिए महिलाओं के शारीरिक शोषण के मामलों में भी राजनीतिक दलों को पॉश एक्ट 2013 जैसे महत्वपूर्ण कानून के दायरे में लाना बदलते हाई टेक वक्त की मांग है और इससे उन्हें छूट देने से समाज की मानसिकता पर गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मामलों में नेताओं के बचने की पूरी संभावना मौजूदा कानून में उपलब्ध है, जो सवालों के घेरे में है। इसलिए इसे और अधिक व्यापक व प्रभावशाली बनाने की जरूरत है। यही महिलाओं की मांग भी है।

क्या भारत की 'घर में घुसकर मारने' की नीति पर असर डालेगा सऊदी-पाक करार?

पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा करार कर लिया है इससे पाकिस्तान यह सोच रहा होगा कि अब किसी आतंकी वारदात के बाद भारत उसे घर में घुस कर मार नहीं पायेगा। यदि ऐसा है तो पाकिस्तान की यह सोच गलत है कि क्योंकि भारत कह चुका है कि हमले का बदला घर में घुस कर लिया जायेगा और यही अब 'न्यू नॉर्मल' है। देखा जाये तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत को पता था कि पाकिस्तान को बचाने के लिए उसके दोस्त चीन और तुर्की आयेंगे लेकिन फिर भी भारत ने घर में घुस कर मारा। इसी तरह बालाकोट एअर स्ट्राइक से पहले भारत को पता था कि पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन पीछे से उसका साथ देगा फिर भी भारत ने घर में घुस कर मारा। इसी प्रकार, भारत को सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पता था कि पाकिस्तान को बचाने के लिए आतंकवादी संगठन और उसके आका तथा चीन सामने आयेंगे लेकिन भारत ने फिर भी घर में घुस कर मारा। इसलिए पाकिस्तान चाहे सऊदी अरब से रक्षा संबंध बना ले या फिर दुनिया की किसी भी दूसरी शक्ति से रक्षा करार कर ले, भारत की नीति स्पष्ट है कि यदि उसके खिलाफ कोई हमला हुआ तो हम राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए घर में घुस कर बदला लेंगे चाहे सामने एक दुश्मन हो या दुश्मन के एक दर्जन साथी भी साथ हों।

यहां यह भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा करार तो कर लिया है लेकिन सऊदी अरब की सैन्य ताकत भारतीय सेना के सामने कितनी प्रभावी है। हम आपको बता दें कि भारत की सेना वर्तमान में लगभग 1.45 मिलियन सक्रिय और 2.1 मिलियन आरक्षित सैनिकों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। इसमें थलसेना, नौसेना, वायुसेना और विशेष बल शामिल हैं। इसके विपरीत, सऊदी अरब की सेना 2.5-2.6 लाख सक्रिय सैनिकों और कुछ हजार आरक्षित बलों पर आधारित है। स्पष्ट है कि केवल संख्या के हिसाब से भी भारतीय सेना कई गुना बड़ी और विविधीकृत है।

इसके अलावा, भारतीय थलसेना के पास ऊ-90 और अर्जुन टैंकों जैसी आधुनिक सामरिक क्षमताएं हैं और यह भारी आर्टिलरी और अनुभवी पैदल सेना से लैस है। दूसरी ओर, सऊदी सेना आधुनिक हथियारों के बावजूद अपने युद्ध अनुभव में सीमित है। यमन के संघर्षों ने इसे पूरी तरह उजागर किया है कि केवल हथियारों की मौजूदगी किसी सैन्य ताकत को अजेय नहीं बनाती।

इसके अलावा, भारतीय सेना स्वदेशी रक्षा तकनीक, परमाणु तंत्र, बैलिस्टिक मिसाइल और साइबर क्षमता में आत्मनिर्भर है। इसके विपरीत, सऊदी अरब भारी निवेश के बावजूद विदेशी तकनीक पर निर्भर है। इसके एंटी-मिसाइल सिस्टम और आधुनिक विमान उतने प्रभावी नहीं हैं, जितना कि उनके बजट से प्रतीत होता है। सऊदी अरब ने देशभक्त और थाड जैसी प्रणालियाँ तैनात की हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल खतरों से सुरक्षा देती हैं। फिर भी यमन के हौथी विद्रोहियों द्वारा ड्रोन और मिसाइल हमलों ने यह साबित किया कि यह कवच पूरी तरह अभेद्य नहीं है।

देखा जाये तो असली ताकत का निर्धारण केवल हथियार और बजट से नहीं होता। भारत ने कई युद्धों और हाल के सीमाई तनावों में वास्तविक अनुभव और रणनीतिक समझ का परिचय दिया है। सऊदी अरब के पास यह अनुभव ही नहीं है। भारत के पास रणनीतिक स्वतंत्रता और निर्णायक क्षमता है, जबकि सऊदी अरब को लंबी लड़ाइयों में विदेशी समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। कुल मिलाकर देखें तो सऊदी अरब की सेना तकनीकी रूप से आधुनिक और बजट में बड़ी जरूर है, लेकिन भारतीय सेना की तुलना में कमज़ोर, अनुभवहीन और विदेशी सहायता पर निर्भर है। भारतीय सेना के पास संख्या, विविधता, सामरिक अनुभव और आत्मनिर्भरता की वजह से निर्णायक श्रेष्ठता है। किसी भी संभावित संघर्ष में भारत की 'घर में घुसकर बदला' नीति को चुनौती देना आसान नहीं होगा।

सच यही है कि सऊदी-पाक समझौता पाकिस्तान को आंशिक आत्मविश्वास दे सकता है, लेकिन भारतीय सामरिक दृष्टिकोण और युद्ध अनुभव उसे क्षेत्रीय परिदृश्य में हमेशा प्रमुख बनाए रखेंगे। देखा जाये तो आधुनिक युद्ध और रणनीति केवल चमक-दमक से तय नहीं होती; असली ताकत अनुभव, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक सोच में निहित होती है और इन मामलों में भारत सऊदी अरब से कहीं आगे है।

साथ ही, यह भी यथार्थ है कि सऊदी अरब की खुद की रणनीतिक प्राथमिकताएँ भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर केंद्रित हैं। हम आपको बता दें कि भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते केवल तेल आयात और प्रवासी भारतीयों तक सीमित नहीं हैं। बीते वर्षों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बढ़ा है। सऊदी अरब भारत का रणनीतिक साझेदार है और दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर कई समझौते किए हैं। भारत सऊदी को एक स्थिर साझेदार के रूप में देखता है और सऊदी को भी भारत की आर्थिक और तकनीकी शक्ति की आवश्यकता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देता भी है तो उस परिस्थिति में भी भारत के लिए अवसर हैं। इज़रायल और ईरान जैसे देशों के साथ गहरे सामरिक संबंध भारत के लिए एक संतुलनकारी भूमिका निभा सकते हैं।

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा करार को भारत के लिए चिंताजनक बता रहे लोगों को यह भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब की सैन्य मदद पर निर्भर रहा है। सऊदी ने उसे वित्तीय पैकेज दिए हैं और कभी-कभी तेल आपूर्ति में रियायतें भी दी हैं। नए रक्षा करार से पाकिस्तान को यह भरोसा मिल सकता है कि सऊदी अरब उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो सऊदी अरब भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करने का जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि भारत न केवल एक बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है बल्कि निवेश और व्यापार का भी अहम बाज़ार है। जहां तक सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की बात है तो उसे इस तरह देखा जा सकता है कि दशकों से दोनों देशों के बीच जो सुरक्षा सहयोग अनौपचारिक स्तर पर चलता रहा, अब उसे एक औपचारिक रूप प्रदान कर दिया गया है। इस समझौते की सबसे अहम धारा यह है कि किसी एक देश पर आक्रमण, दोनों पर आक्रमण माना जाएगा। पाकिस्तान के लिए यह समझौता कई स्तरों पर महत्व रखता है। सबसे पहले, यह उसे एक प्रकार की रणनीतिक सुरक्षा गारंटी प्रदान करता है। अफगानिस्तान की अस्थिरता और भारत के साथ निरंतर तनावपूर्ण रिश्तों के बीच, सऊदी अरब जैसा शक्तिशाली सहयोगी औपचारिक रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इससे पाकिस्तान का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह अपने पड़ोसियों पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा।

दूसरे, यह संधि पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक सहयोग की नई राहें खोलती है। उसकी डगमगाती अर्थव्यवस्था और सीमित रक्षा संसाधनों के बीच सऊदी अरब से संभावित वित्तीय व तकनीकी सहयोग राहत देगा। अब तक पाकिस्तान ने 8, 000 से अधिक सऊदी सैन्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया है। इस समझौते से संयुक्त अभ्यास और हथियार प्रणालियों का आदान-प्रदान और गहरा हो सकता है। तीसरे, यह समझौता पाकिस्तान की इस्लामी दुनिया में कूटनीतिक हैसियत को मजबूती देता है। लंबे समय से पाकिस्तान खुद को इस्लामिक जगत का प्रतिनिधि मानने की कोशिश करता रहा है। सऊदी अरब, जो इस्लामी देशों का परंपरागत नेता माना जाता है, यदि पाकिस्तान के साथ औपचारिक रक्षा-संधि करता है तो इस्लामिक मंचों पर पाकिस्तान की स्थिति स्वाभाविक रूप से मजबूत होती है।

इसके अलावा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा करार को यदि अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें अमेरिका और चीन दोनों की भूमिका भी अहम होगी। अमेरिका पारंपरिक रूप से सऊदी सुरक्षा का संरक्षक रहा है, जबकि चीन पाकिस्तान का निकटतम सामरिक सहयोगी है। यदि यह समझौता व्यावहारिक रूप में गहराता है, तो यह दोनों महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का नया मंच भी बन सकता है। इज़रायल कारक को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ओर सऊदी अरब इज़रायल के साथ संभावित सामान्यीकरण की ओर कदम बढ़ा रहा था, दूसरी ओर पाकिस्तान इज़रायल विरोध की राजनीति करता है। भारत, जो इज़रायल का करीबी सुरक्षा साझेदार है, इस नए समीकरण में एक संवेदनशील स्थिति में आ सकता है।

बहरहाल, यह समझौता भारत के लिए रणनीतिक परीक्षण भी है। यह भारत को यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में किस प्रकार वह अपनी सुरक्षा, ऊर्जा और कूटनीतिक हितों को संतुलित रखते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। यहां एक बात और समझनी होगी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता 'किसी भी आक्रमण' की बात कर रहा है लेकिन इतिहास बताता है कि भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया बल्कि पलटवार किया है। आगे भी यदि कोई स्थिति बनी तो बदला लेने में कोई करार भारत के रास्ते की बाधा नहीं बनेगा।

टेट प्रकरण में प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा जनपद प्रयागराज संबंध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश द्विवेदी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबोधित ज्ञापन भेजकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टेट संबंधित मामले में अव्यवहारिक फैसले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि लाखों शिक्षकों को निराशा व परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार अपने स्तर से संशोधित शासनादेश जारी करें।अपर जिला अधिकारी प्रयागराज नगर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। जिसमें जिले के तमाम पदाधिकारी एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। सभा को प्रदेश की संगठन मंत्री श्रद्धा श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया।जिला उपाध्यक्ष देवव्रत द्विवेदी, जिला संगठन मंत्री अलका सेठ, संगठन मंत्री सतीश तिवारी, उपेंद्र द्विवेदी, शिक्षामित्र संघ के जिला अध्यक्ष वसीम अहमद, संतोष तिवारी, सुनील तिवारी , अरविंद यादव श्यामा कांत द्विवेदी, सुनील कुमार शुक्ला, आशीष जायसवाल, शाहिद सहित जिला कार्यकारिणी व ब्लाक कार्यकारिणी के सदस्य तथा शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

जनता को गुमराह करने के साथ संवैधानिक संस्थाओं का गला घोट रहे हैं राहुल गांधी : मेघवाल

प्रयागराज आगमन पर केंद्रीय राज्य मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल का किया स्वागत

प्रयागराज। केंद्रीय राज्य मंत्री केंद्रीय कार्य संसदीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का प्रयागराज आगमन पर आर्य कन्या डिग्री कॉलेज मुट्ठीगंज में स्वागत किया।

मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी के अनुसार इस बीच पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय कार्य संसदीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार-बार वोट चोरी के नाम पर झूठ बोलकर चुनाव आयोग के ऊपर गलत आरोप लगाकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और एक षड्यंत्र के तहत भारत के अंदर बांग्लादेश और नेपाल की जैसी स्थिति पैदा करना चाह रहे उन्होंने कहा जब जनता उन्हें नहीं जीता रही है तो लोकतंत्र की हत्या करके जबरन सत्ता पर काबिज होना चाह रहे हैं है और कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है।

इसलिए वह हताश और परेशान है और जब राहुल गांधी से उनके द्वारा लगाए गए आरोपी को प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है तो वह भाग खड़े होते हैं।

उन्होंने इसके पहले भी कई आरोप लगे जिसकी वजह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ी है उन्होंने कहा कि जब लोकसभा के चुनाव में वोट चोरी हुई है तो राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से कैसे चुनाव जीत गए क्या उन्होंने वोट की चोरी की थी अगर की थी तो वे देश की जनता को बताएं और कहा कि बिहार की जनता आने वाले

विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी को उनके द्वारा दुष्प्रचार किए जाने पर बिहार की जनता उन्हें बुरी तरह हराकर करके सबक सिखाएगी और कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और भारत पूरे विश्व में चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की समरी शक्ति बड़ी है जिसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बौखलाहट के शिकार हो चुके हैं एक तरफ वह मोदी को अपना मित्र मानते हैं दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ लगाकर भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं लेकिन भारत झुकने वाला नहीं है भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर संकट से उबरना जानता है।

उन्होंने पत्रकारों से कहा राहुल गांधी एक तरफ संविधान की बात को करते और दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं का गला घोट रहे और बदनाम कर रहे हैं और कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है अपने फायदे के लिए संविधान की हत्या करना इसका प्रमाण है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपना चुनाव बढ़ाने की खातिर देश के अंदर आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की और संविधान की हत्या की लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जरूरत के हिसाब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सभी दलों से चर्चा करते हुए संविधान में संशोधन किया है। मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने बताया कि इस अवसर पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी , एम एल सी सुरेंद्र चौधरी , प्रवक्ता राजेश केसरवानी कुमार नारायण, पूर्व पार्षद विजय पुर्शवानी, अतुल खन्ना, अजय अग्रहरि, शत्रुघ्न जायसवाल, गौरी शंकर वर्मा पार्षद अजय हेला मनु कक्कड, आदि भाजपा कार्यकर्ताओ ने स्वागतकिया।

गायत्री ज्ञान मंदिर के ज्ञान यज्ञ अभियान के अन्तर्गत 448वाँ युगऋषि वाङ्मय की स्थापना सम्पन्न

प्रयागराज। गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर, लखनऊ के विचार क्रान्ति ज्ञान यज्ञ अभियान के अन्तर्गत ''टी0आर0सी0 महाविद्यालय, सतरिख, बाराबंकी, उ0प्र0'' के पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक युगऋषि पं0 श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित सम्पूर्ण 79 खण्डों का 448वाँ ऋषि वाङ्मय की स्थापना का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। उपरोक्त साहित्य गायत्री परिवार की सक्रिय कार्यकर्त्री श्रीमती पुष्पा सिंह ने अपने पौत्र दीपांश सिंह के उज्ज्वल भविष्य के लिए भेंट किया तथा उपस्थित संकाय सदस्यों एवं छात्र-छात्राओं को अखण्ड ज्योति (हिन्दी) पत्रिका भेंट की। इस अवसर पर वाङ्मय स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने कहा कि 'ज्ञानदान युगधर्म है।' गायत्री परिवार की श्रीमती उषा सिंह एवं देवेन्द्र सिंह ने भी अपने विचार रखे। संस्थान के प्राचार्य डॉ0 आदेश तिवारी, निदेशक प्रशासक सचिन सक्सेना एवं प्रबन्धक डॉ0 रंजन मिश्रा ने अपने विचार व्यक्त किये। श्रीमती वीवा नाज ने मंच का संचालन किया।

इस अवसर पर गायत्री ज्ञान मंदिर के प्रतिनिधि उमानंद शर्मा, देवेन्द्र सिंह, श्रीमती उषा सिंह, श्रीमती पुष्पा सिंह एवं संस्थान के प्रबोध सिंह प्रशासनिक अधिकारी, डॉ0 गिरिजा शंकर वर्मा, डॉ0 शुचिता चतुर्वेदी सहित संस्थान की शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्रायें मौजूद रहे।

नवागन्तुक पुलिस उपायुक्त नगर कमिश्नरेट प्रयागराज मनीष कुमार शांडिल्य द्वारा आज दिनांक- 19.09.2025 को पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई कर फरियादियों की शिकायतें सुनी गयीं तथा उनके समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

हिन्दी पखवाड़ा में बुलंदी संस्था द्वारा पीएमविद्यालय पालपुर में प्रतियोगिता आयोजित

प्रयागराज। पीएम कम्पोजिट विद्यालय पालपुर विकास खंड चाका प्रयागराज में हिन्दी दिवस पखवाड़े के अन्तर्गत बुलन्दी साहित्यिक संस्था उत्तराखंड द्वारा निबंध और चित्रांक प्रतियोगिता आयोजित किया गया।जूनियर स्तर की निबंध प्रतियोगिता में अंश निषाद और शौर्य निषाद कक्षा-8 , रिया निषाद और सरस कक्षा -7 ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।बजरंगी कक्षा -8 और आभास -7 द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

चित्रांकन में कक्षा 8 की सोनाक्षी, शिवानी, कक्षा -7 की जाह्नवी, रिया प्रजापति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा -6 से विभा और रिया कन्नौजिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।यह प्रतियोगिता संस्था के अध्यक्ष बादल बाजपुरी, संरक्षक पंकज शर्मा और राष्ट्रीय महामंत्री भारतेन्द्र त्रिपाठी के दिशा निर्देश में प्रतियोगिता आयोजित की गई।सभी को प्रधानाध्यापिका उषा शर्मा ने मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।इस अवसर पर आभा श्रीवास्तव, मधुलता, सुलोचना, ममता शर्मा आदि विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।

हिंदी विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं वित्ताधिकारी ने विद्यार्थियों को दिया खेल का पुरस्कार

प्रयागराज। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज में खेल दिवस पर आयोजित हुए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण कुलसचिव एवं वित्ताधिकारी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कुलसचिव कादर नवाज़ खान ने कहा कि यहां आने के बाद उन्हें लगा कि यह केंद्र एक छोटा सा परिवार जैसा है, शिक्षक और विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोई भी काम हो उसमें जिजीविषा का भाव बनाए रखिए। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वित्ताधिकारी पी. एस. सिंह ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने क्षेत्रीय केंद्र को आगे बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्र के अकादमिक निदेशक प्रोफेसर अखिलेश कुमार दुबे ने कहा कि हमारे पास संसाधनों की कमी है पर हौसले की नहीं। हर खिलाड़ी को जोश बना के रखना चाहिए।

खेल दिवस पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में समाजकार्य के प्रशांत पांडेय प्रथम, जनसंचार की आयुषी उपाध्याय, फिल्म अध्ययन के हिमांशु चौरसिया द्वितीय स्थान तथा जनसंचार की प्रज्ञा भारती एवं दीक्षा द्विवेदी को तृतीय स्थान मिला। स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जनसंचार के दीक्षा द्विवेदी , द्वितीय प्रज्ञा भारती एवं तृतीय स्थान आयुषी उपाध्याय एवं हिमांशु चौरसिया को मिला। बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजनीति विज्ञान की स्वाति पांडेय, द्वितीय स्थान जनसंचार की दीक्षा द्विवेदी एवं तृतीय स्थान आयुषी उपाध्याय एवं प्रज्ञा भारती को मिला। इस अवसर पर फिल्म अध्ययन विभाग के विद्यार्थियों द्वारा निर्मित फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। यह फिल्म मोहन राकेश द्वारा रचित आधे-अधूरे नाटक के एक दृश्य का सिनेमा रूपांतरण है। इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता के संयोजन डॉ. सत्यवीर मौजूद रहे। रस्सी कूद, नींबू दौड़ और प्लैंक के संयोजक डॉ. यशार्थ मंजुल मौजूद रहे। तिरंगा रंगोली प्रतियोगिता की संयोजक डॉ. विजय सिंह मौजूद रही। बैडमिंटन के संयोजक डॉ. अख्तर आलम मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन समाज कार्य के सहायक आचार्य डॉ. मिथिलेश तिवारी तथा आभार ज्ञापन अनुवाद विभाग के डॉ सत्यवीर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर समीर अवस्थी, जयेंद्र जायसवाल, सुभाष श्रीवास्तव, राहुल, रश्मि, प्रत्यूष, श्रीमती गीता देवी, देवमूर्ति द्विवेदी, बिरजू प्रसाद, जगजीवनराम प्रजापति, रोहित कुमार, पीतांबर गौतम, अभिषेक कुमार सहित केंद्र के शोधार्थी मीनू त्रिपाठी, दीपेश कुमार एवं विद्यार्थी अनुज, प्रशांत, प्रभात, प्रज्ञा, दीक्षा, आयुषी, स्वाति, राजकुमार, अनन्या, विकलेश उपस्थित रहे।

विकसित भारत' थीम पर चित्रकला प्रतियोगिता, कलाकारों ने दिखाई प्रतिभा

प्रयागराज। रंगों और कूचियों ने जब 'विकसित भारत' का सपना साकार किया तो इलाहाबाद संग्रहालय का हर कोना कला और सृजन की छटा से भर उठा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र एवं इलाहाबाद संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को सेवा पर्व के तहत आयोजित एक दिवसीय चित्रकला प्रतियोगिता में लगभग 500 से अधिक कलाकारों ने अपनी कल्पनाओं को कैनवास पर उतारा। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय न्यायमूर्ति सुधीर नारायण (सेवानिवृत्त) ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल आर्टिस्ट शामिल हुए, जिन्होंने डिजिटल क्रांति, यूपीआई, आधार, चंद्रयान-3, आदित्य-एल1, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर मनमोहक चित्र बनाए। इन रचनाओं ने विकसित भारत की दिशा में हो रही प्रगति का सजीव चित्रण किया। विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए हमें अपनी संस्कृति और धरोहरों की गहरी समझ जरूरी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूती में कला और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका है। न्यायमूर्ति सुधीर नारायण (सेवानिवृत्त) ने कलाकारों की कृतियों को समाज में बदलाव की ताकत बताया। केंद्र निदेशक सुदेश शर्मा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं युवा कलाकारों को प्रतिभा दिखाने और आत्मविश्वास बढ़ाने का मंच देती हैं। विजेताओं की घोषणा आगामी 2 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में की जाएगी।

इस अवसर पर ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय सचिव देवेंद्र त्रिपाठी, इलाहाबाद संग्रहालय के निदेशक राजेश प्रसाद, समाजसेवी सुबंधु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग के अध्यक्ष अजय जेतली और सुनमिता मलिक एवं केंद्र के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कल्पना सहाय ने किया।

नलकूप की मोटर जलने से किसानों की फसलें सूखने की कगार पर

थरवई। सोराम विकासखंड के ग्राम पंचायत जगदीशपुर पूरे चंदा में लगे राजकीय नलकूप संख्या पाँच एस की मोटर एक बार फिर जल जाने से किसानों की धान की फसल पर संकट गहराता जा रहा है। मोटर खराब होने से किसानों को खेतों की सिंचाई में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीण किसानों का कहना है कि यह मोटर लगभग प्रतिमाह जल जा रही है, जिससे समय-समय पर उनकी फसलें सूखने की स्थिति में पहुंच जाती हैं। किसान काशी नरेश शुक्ला, ननकू पांडे और ग्राम प्रधान रामू तिवारी ने बताया कि इस नलकूप से करीब तीस बीघा क्षेत्रफल में बोई गई धान की फसल के साथ-साथ अन्य खरीफ फसलें भी खराब हो रही हैं।किसानों ने बताया कि मोटर खराब होने के कारण उन्हें निजी साधनों से सिंचाई करनी पड रही है, जिससे अतिरिक्त खर्च का बोझ भी बढ़ रहा है। वहीं, कई छोटे किसान पानी न मिलने से खेतों को सूखा छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।ग्रामीणों ने नलकूप विभाग प्रखंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग की है कि नलकूप को तत्काल दुरुस्त कराया जाए।

हिन्दी सप्ताह के अंतर्गत काव्यपाठ का हुआ आयोजन

प्रयागराज। इफको घियानगर फूलपुर में हिंदी सप्ताह के अंतर्गत काव्य पाठ का आयोजन सामुदायिक केन्द्र में हुआ। काव्य पाठ में इफको कर्मचारी, महिलाएँ तथा बच्चों ने संस्कृति, प्रकृति, देशभक्ति और सामाजिक मुद्दों जैसे विषयों पर हिंदी कविताएँ प्रस्तुत कीं, जो श्रोताओं और निर्णायकों को प्रेरित करने वाली थीं।यह प्रतियोगिता न केवल हिंदी भाषा का उत्सव थी, बल्कि कविता के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का भी एक प्रयास था।'कार्यक्रम का संचालन हेमलता सिजोरिया ने किया। इस दौरान महाप्रबंधक रत्नेश कुमार, संयुक्त महाप्रबंधक क्रमशः ए.के.गुप्ता एवं पी.के. वर्मा, इफको ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग तिवारी , महामंत्री स्वयम् प्रकाश , इफको इंप्लॉयी यूनियन के महामंत्री विजय कुमार यादव तथा बड़ी संख्या में घियानगरवासी मौजूद रहे।

हिंदी प्रकोष्ठ के तत्वावधान में हिंदी पखवाड़ा का हुआ आयोजन

प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.एन.एन.आई.टी.), इलाहाबाद, प्रयागराज में हिंदी प्रकोष्ठ के तत्वावधान में हिंदी पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस श्रृंखला में संस्थान के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी कविता वाचन प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए एक से बढ़कर एक कविताओं का वाचन किया। काव्य-पाठ की प्रस्तुतियों ने वातावरण को भावपूर्ण बना दिया। इस अवसर पर तौशीफ अहमद की कविता को विशेष सराहना प्राप्त हुई और श्रोताओं ने उनके प्रस्तुतीकरण को अत्यंत प्रभावशाली बताया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संस्थान के कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा दैनिक कार्यों में हिंदी को सरल एवं सुलभ बनाना था। प्रतियोगिता का संचालन सहायक कुल सचिव सत्यजीत कुमार ने किया। निर्णायक मंडल में सहायक निदेशक (राजभाषा) प्रमोद कुमार द्विवेदी एवं मो. दानिश सम्मिलित रहे, जिन्होंने प्रस्तुतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया। हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता ने न केवल कर्मचारियों में साहित्यिक अभिरुचि को प्रोत्साहित किया, बल्कि राजभाषा हिंदी के प्रति उनकी अभिव्यक्ति और जुड़ाव को भी सशक्त बनाया।

Gen Z बयान पर बवाल, फडणवीस बोले- राहुल गांधी ने अर्बन नक्सल सोच का सबूत दिया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राहुल गांधी के जेनरेशन ज़ेड और वोट चोरी वाले पोस्ट ने भाजपा को नाराज़ कर दिया है। भाजपा अब राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। सबसे तीखा प्रहार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया, जिन्होंने अब उन्हें शहरी माओवादी करार दिया है और कहा कि उनका दिमाग चुरा लिया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'यह 'वोट चोरी' का मामला नहीं है, बल्कि राहुल गांधी जी के दिमाग की चोरी का मामला है... उन्होंने अपने 'शहरी माओवादी' होने का सबूत दे दिया है जब उन्होंने कहा कि जेन-जेड को एक संवैधानिक सरकार को गिराना चाहिए...।'

कथित वोट चोरी के आरोपों के अपने दूसरे दौर के बाद, गांधी ने शाम को एक्स पर पोस्ट किया था कि देश के छात्र, युवा और जेनरेशन ज़ेड 'संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी रोकेंगे' और वह उनके साथ खड़े हैं। 'जेनरेशन ज़ेड'–वह पीढ़ी जिसने पड़ोसी देश नेपाल में सत्तारूढ़ सरकार को उखाड़ फेंकने वाले विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था–का ज़िक्र होने पर भाजपा ने कड़ी आलोचना की

थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को राहुल गांधी के जनरेशन ज़ी वाले पोस्ट की आलोचना की, जिसमें वोट चोरी का दावा किया गया था।

एएनआई से बात करते हुए, दुबे ने दावा किया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत में गृहयुद्ध भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि गांधी देश को बांटने के लिए सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दुबे ने एएनआई को बताया कि राहुल गांधी भारत में गृहयुद्ध भड़काना चाहते हैं... वह देश को बांटने के लिए सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अन्ना हजारे आंदोलन और निर्भया कांड जैसी घटनाओं को याद करते हुए, भाजपा सांसद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत में जनरेशन ज़ी ने कई बार देश की तकदीर बदली है। दुबे ने तर्क दिया कि जेन ज़ेड का मतलब अगली पीढ़ी, युवा और वे अपने देश के बारे में कैसे फ़ैसला लेना चाहते हैं और सरकार बदलना चाहते हैं। जेन ज़ेड भारत में पहले ही ऐसा कर चुका है। अन्ना और अरविंद केजरीवाल का आंदोलन जेन ज़ेड का ही नतीजा था... निर्भया कांड के दौरान, 2013 में एक लाख लोग सड़कों पर थे।

इसके अलावा, उन्होंने विपक्ष के नेता पर बांग्लादेश और नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों से कथित तौर पर जुड़ने का आरोप लगाते हुए उनकी कड़ी आलोचना की। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी नेपाल और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उससे खुद को जोड़ना चाहते हैं। दोनों ही जगहों पर, जेन ज़ेड भाई-भतीजावाद और 'परिवारवाद' के खिलाफ़ था... 'परिवारवाद' कहाँ है?... यह गांधी परिवार में दशकों से है... अगर वह जेन ज़ेड को भड़काना चाहते हैं, तो मैं राहुल गांधी के साथ हूँ; पूरी कांग्रेस पार्टी को देश छोड़कर भागना होगा... नेपाल और बांग्लादेश में, जेन ज़ेड भ्रष्टाचार के खिलाफ़ था... सभी घोटाले कांग्रेस ने किए हैं।

वाहन की टक्कर से पैदल राहगीर की मौत, चालक फरार

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी के मानकोली नाका क्षेत्र में गुरुवार रात हुए सड़क हादसे में एक पैदल राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामले में अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मृतक की पहचान मोहम्मद काशिम अब तालीब शेख (25) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार काशिम भोईवाड़ा इलाके में रहता था और गुरुवार रात करीब 11 बजे काम से घर लौट रहा था। इसी दौरान अज्ञात ट्रक ने तेज रफ्तार से ओवरटेक करते हुए उसे जोरदार टक्कर मारी। हादसे में काशिम गंभीर रूप से घायल हुआ और अत्यधिक रक्तस्राव के चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई।घटना की जानकारी मिलते ही नारपोली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को स्व. इंदिरा गांधी उपजिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बड़े भाई आसिफ शेख की शिकायत पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से फरार चालक की तलाश में जुटी है।

अदानी विलमर का नकली तेल बेचने वाले व्यापारी पर मामला दर्ज

भिवंडी। भिवंडी शहर में नकली तेल बेचने का मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने खड़क रोड स्थित एक गोदाम से अदानी विलमर कंपनी के हूबहू रंगसंगति वाले नकली तेल के पैकेट जब्त किए हैं। इस सिलसिले में निजामपुरा पुलिस स्टेशन में एक व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी का नाम अब्दुल हकीम शमशुलकुमार अंसारी (37) है, जो इस्लामपुरा, निजामपुरा इलाके में रहता है। जानकारी मिली थी कि वह अदानी विलमर कंपनी के नकली तेल का उत्पादन कर उसकी बिक्री कर रहा है.18 सितंबर को पुलिस ने खड़क रोड स्थित कुवारी कंपाउंड में प्रकाश ऑयल गोदाम पर छापा मारा। जांच में पाया गया कि अब्दुल ने अदानी विलमर के नाम पर नकली तेल तैयार कर बिक्री के लिए रखा था। इससे कंपनी के स्वामित्व और कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में नरेंद्र विजय वेडवाला की शिकायत पर निजामपुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 103 और 104 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

बार डांसर से छेड़छाड़ के आरोप में दो बार मालिकों पर मामला दर्ज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी के काल्हेर इलाके में एक 19 वर्षीय बार डांसर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर नारपोली पुलिस ने दो बार मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी बार मालिकों के नाम हरीश उर्फ अरुण चिन्ना पुजारी (42) और चिदानंद आनंद गौड़ हैं। दोनों

काल्हेर स्थित सुकूर बार के संचालक बताए जाते हैं। पीड़िता भिवंडी बायपास स्थित किनारा बार में गायिका के रूप में काम करती है और आरोपी हरीश के फ्लैट में किराए से रहती है।घटना 16 सितंबर की रात करीब डेढ़ बजे की है। शिकायत में कहा गया है कि पीड़िता अपने दो दोस्तों के साथ कमरे में बैठकर बातचीत कर रही थी। तभी हरीश और चिदानंद वहां पहुंचे। उन्होंने पहले पीड़िता के दोस्तों को गाली-गलौज की और उसके चरित्र पर सवाल उठाए। इसके बाद दोनों ने पीड़िता से अभद्र भाषा में बात की और चेतावनी दी कि अगर वह दोबारा दोस्तों को घर बुलाएगी तो उसे निकाल दिया जाएगा। इसी दौरान आरोपियों ने उसका विनयभंग किया। पीड़िता की शिकायत पर 19 सितंबर को नारपोली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

रेलवे बोर्ड के सदस्य (इन्फ्रास्ट्रक्चर) नवीन गुलाटी का अहमदाबाद मंडल दौरा

साबरमती स्टेशन पर चल रहे विभिन्न पुनर्विकास कार्यों का किया निरीक्षण

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रेलवे बोर्ड के सदस्य (इन्फ्रास्ट्रक्चर) नवीन गुलाटी ने 19 सितंबर, 2025 को पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद स्थित साबरमती रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्री गुलाटी ने स्टेशन परिसर में लगाए गए लघु मॉडल का अवलोकन किया, जिसमें पुनर्विकसित स्टेशन का प्रस्तावित स्वरूप दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने साबरमती स्टेशन के जेल साइड क्षेत्र एवं मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब का भी निरीक्षण किया जो बहु-मॉडल परिवहन केंद्र के रूप में पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य परिवहन के आगामी और मौजूदा साधनों को एकीकृत करना है जिसमें रेलवे, सिटी मेट्रो नेटवर्क, हाई स्पीड रेल नेटवर्क, सिटी BRT बस नेटवर्क और सिटी बस सेवाएं शामिल हैं। स्टेशन परिसर को बहु-मॉडल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के कारण यहां यात्रियों की आवाजाही अधिक होगी साथ ही यात्री सुविधाओं के विस्तार और निर्माण गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री गुलाटी ने यह भी बताया कि साबरमती स्थित इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो में वंदे भारत ट्रेनसेट्स के मेंटेनेंस का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जो वर्ष 2025 के अंत तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। इसके बाद इस डिपो में और अधिक वंदे भारत ट्रेनों का पीरियॉडिक ओवरहॉल एवं मेंटेनेंस कार्य किया जा सकेगा। उन्होंने रेलवे के भविष्य की योजनाओं की ओर संकेत करते हुए कहा कि रेलवे यात्री सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है और इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा डिजिटल तकनीकों का भरपूर

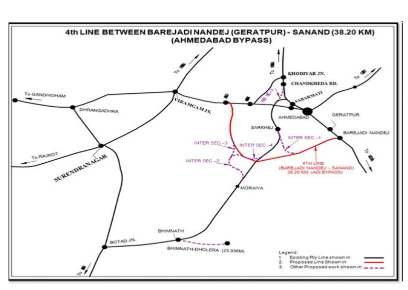

उपयोग किया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान श्री गुलाटी ने मण्डल के वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ अहमदाबाद मण्डल में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने जानकारी दी कि साबरमती से सरखेज के बीच प्रस्तावित नई ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। यह रेल लाइन भविष्य में अहमदाबाद क्षेत्र में रेल यातायात का दबाव कम करने में सहायक होगी। रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी तथा ट्रेनों की गति में वृद्धि करने में सहायक होगी।

साबरमती-सरखेज दोहरीकरण परियोजना 21 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग को कवर करती है, जिसके अंतर्गत साबरमती डी केबिन से सरखेज तक मौजूदा रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जा रहा है। यह नई ब्रॉड गेज (बीजी) दोहरी लाइन मौजूदा लाइन के समानांतर बिछाई जाएगी। यह लाइन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति क्षमता के अनुरूप डिज़ाइन की गई है, जो इस मार्ग के भारी उपयोग और यात्री एवं माल ढुलाई–दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी। यह परियोजना प्रस्तावित सरखेज-धोलेरा नई ब्रॉड गेज दोहरी लाइन के लिए एक प्रमुख प्रस्थान बिंदु के रूप में भी कार्य करेगी, जिससे क्षेत्रीय रेलवे नेटवर्क और अधिक सशक्त होगा। वर्तमान में इस मार्ग पर माल ढुलाई 2.46 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है, जो परियोजना के चालू होने के पहले वर्ष में 4.65 एमटीपीए और ग्यारहवें वर्ष तक बढ़कर 15.05 एमटीपीए तक पहुँचने का अनुमान है। इस मार्ग में गांधीग्राम, वस्त्रापुर और सरखेज तीन स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा, परियोजना में 16 छोटे पुल, 13 लिमिटेड हाइट सबवे (एलएचएस), 8 लेवल क्रॉसिंग और चांदलोडिया के पास एक रेल फ्लाईओवर (आरएफओ) का निर्माण भी प्रस्तावित है।

साबरमती-सरखेज दोहरीकरण परियोजना इस क्षेत्र में रेलवे क्षमता के विस्तार और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो मजबूत रेलवे अवसंरचना के माध्यम से दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी।

अहमदाबाद बाईपास के हिस्से के रूप में बारेजड़ी नांदेज (गेरतपुर) और साणंद के बीच 38.20 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। इस परियोजना को ?961.67 करोड़ की लागत से मंजूरी दी गई है। साबरमती नदी पर 30.5 मीटर लंबे 26 स्पैन वाला एक बड़ा पुल वर्तमान में निर्माणाधीन है। सिविल कार्यों के लिए दो टेंडर खोले गए हैं, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है; पाँच गाँवों के लिए भूमि आवंटन पहले ही किया जा चुका है, जबकि शेष गाँवों के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

मैसूर दशहरा उत्सव में बानू मुश्ताक ही रहेंगी चीफ गेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी, जिसमें मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में राज्य प्रायोजित दशहरा महोत्सव के उद्घाटन के लिए बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 15 सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील एच एस गौरव ने दायर की थी।

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में 'मैसूर दशहरा' उत्सव के उद्घाटन के लिए बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब 2017 में कन्नड़ लेखक निसार अहमद ने दशहरा समारोह का उद्घाटन किया था, उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। न्यायालय ने वर्तमान याचिका के पीछे के उद्देश्य को समझते हुए स्पष्ट किया कि यह एक राज्य द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और संविधान के अनुसार, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश विभु भाकरू और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने चार जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मैसूरु के पूर्व भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा द्वारा दायर याचिका भी शामिल थी। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी संवैधानिक या कानूनी उल्लंघन को साबित करने में विफल रहे हैं।

गौरतलब है कि मैसूर जिला प्रशासन ने विपक्षी भाजपा सहित कुछ वर्गों की आपत्तियों के बावजूद,

3 सितंबर को मुश्ताक को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया था। यह विवाद इस आरोप से उपजा है कि बानू मुश्ताक ने अतीत में ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें कुछ लोग 'हिंदू विरोधी' और 'कन्नड़ विरोधी' मानते हैं। सिम्हा और अन्य आलोचकों का तर्क है कि इस उत्सव के लिए उनका चयन, जो पारंपरिक रूप से वैदिक अनुष्ठानों और देवी चामुंडेश्वरी को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ शुरू होता है, धार्मिक भावनाओं और इस आयोजन से जुड़ी दीर्घकालिक परंपराओं का अनादर करता है। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता के. शशिकिरण शेट्टी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दशहरा उद्घाटन एक राजकीय समारोह है। उन्होंने बताया कि उद्घाटन के लिए आमंत्रित किए जाने वाले व्यक्ति का चयन करने वाली समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ स्थानीय सांसद और विधायक भी शामिल थे।

कवर पर छपी सिगरेट पीने वाली तस्वीर, अरुंधति राय की नई किताब के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। केरल उच्च न्यायालय ने लेखिका अरुंधति रॉय की नवीनतम पुस्तक के कवर पेज को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका (पीआईएल) में रॉय की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 'मदर मैरी कम्स टू मी' के कवर पेज पर छपी तस्वीर पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें लेखिका को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, लेकिन उस पर अनिवार्य वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी नहीं दी गई है। कोच्चि के वकील राजसिम्हन द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि यह तस्वीर धूम्रपान को महिमामंडित करके समाज, खासकर युवतियों और महिलाओं के लिए एक हानिकारक संदेश देती है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक प्रतिष्ठित लेखक को इस तरह से प्रस्तुत करने से यह गलत धारणा बनती है कि धूम्रपान बौद्धिक रचनात्मकता को बढ़ाता है। याचिका में कहा गया है कि पुस्तक के कवर पर सिगरेट पीते हुए लेखक की तस्वीर युवाओं को पूरी तरह से भ्रामक और अस्वास्थ्यकर संदेश देती है कि धूम्रपान फैशनेबल है, बौद्धिक रूप से उत्तेजक है और आंतरिक रूप से रचनात्मकता से जुड़ा है। यह मामला गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की पीठ के समक्ष आया। पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह अदालत को बताए कि क्या ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए कोई एजेंसी या तंत्र मौजूद है। साथ ही, मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित की। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि कवर छवि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 का उल्लंघन करती है, जो तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों तरह के विज्ञापनों पर तब तक रोक लगाता है जब तक कि वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनियाँ न हों। याचिका में कहा गया है कि चेतावनी के बिना छवि प्रदर्शित करना धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का अप्रत्यक्ष प्रचार है।

इस पुस्तक के वर्तमान कवर के साथ इसकी बिक्री, प्रसार और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के अलावा, याचिका में बाजार से इसकी सभी मौजूदा प्रतियों को वापस लेने की भी मांग की गई है। इसमें यह भी घोषित करने की मांग की गई है कि वैधानिक चेतावनी के बिना पुस्तक का प्रकाशन 'अवैध और सीओटीपीए का उल्लंघन' है।

नेपाल की नई अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत विदेश मंत्रालय ने कहा- मिलकर काम करना जारी रखेंगे

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। नेपाल के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आपने इस मामले पर पहले जारी किया गया हमारा बयान देखा होगा। हम नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने नेपाल की प्रधानमंत्री कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के लिए भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। एक घनिष्ठ पड़ोसी, एक लोकतंत्र और एक दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में भारत हमारे दोनों देशों के लोगों और लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।

पीएम मोदी ने बीते दिनों नेपाल की अपनी समकक्ष सुशीला कार्की से बात की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कार्की के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने पड़ोसी देश में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई जनहानि पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती सुशीला कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। हाल ही में हुई जनहानि पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की।

उन्होंने कहा साथ ही मैंने उन्हें और नेपाल की जनता को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं।'' काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार बातचीत के दौरान कार्की (73) ने कहा, 'अंतरिम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता चुनाव ही रहेंगे, तथा जवाबदेह, उत्तरदायी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए दृढ़ संकल्प युवाओं की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा।

अहमदाबाद विमान हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई171 दुर्घटना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने एक याचिका दायर कर दुर्घटना की चल रही जाँच पर गंभीर चिंता जताई है। एनजीओ ने आरोप लगाया है कि जाँच में निष्पक्षता का अभाव है और शुरुआत से ही पक्षपात के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अपनी याचिका में, फाउंडेशन ने माँग की है कि जाँच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए और उड़ान से जुड़े सभी आँकड़े सार्वजनिक किए जाएँ। एनजीओ ने आगे दावा किया है कि प्रारंभिक जाँच के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई, जिनमें ईंधन स्विच की खराबी, विद्युत दोष, रैम एयर टर्बाइन (आरएटी) का संचालन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक विसंगतियाँ शामिल हैं। याचिका में उठाई गई एक और बड़ी चिंता कथित हितों के टकराव की है - जाँच दल में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारी शामिल हैं, जिस पर स्वयं विमानन सुरक्षा में लापरवाही के आरोप हैं। एनजीओ ने ज़ोर देकर कहा कि जाँच पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए और अदालत द्वारा इसकी निगरानी की जानी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके।

ईमेल में दावा, मद्रास उच्च न्यायालय अमेरिकी दूतावास और स्कूल में बम रखा है

चेन्नई **(एजेंसी)**। मद्रास उच्च न्यायालय को शुक्रवार को बम की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के कार्यालय को एक ईमेल भेजा गया था जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिकी दूतावास, मद्रास उच्च न्यायालय और एक स्कूल में आरडीएक्स विस्फोटक रखे गए हैं। धमकी के बाद, बम निरोधक दस्ते ने कर्मचारियों, वकीलों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय परिसर के अंदर कई जगहों की गहन तलाशी ली। अधिकारियों ने जनता से शांत रहने का आग्रह किया है क्योंकि धमकी की उत्पत्ति और विश्वसनीयता की जाँच जारी है।

30 जुलाई को बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया, जब अपार्टमेंट की दीवार पर हमले की चेतावनी वाला एक संदेश लिखा मिला। शहर के कोडिगेहल्ली इलाके में स्थित अल्फाइन पिरामिड अपार्टमेंट में संदेश में लिखा था कि पाकिस्तान से भारत पर हमला होगा। अपार्टमेंट परिसर में लगभग 300 परिवार रहते हैं। जैसे ही यह लिखावट देखी गई, घबराए निवासियों ने पुलिस को सूचित किया। जवाब में, बम निरोधक दल, खोजी कुत्तों के दस्ते और खुफिया विभाग के लोग घटनास्थल पर पहुँचे और परिसर की गहन तलाशी शुरू की। 23 जुलाई को बेंगलुरु के कलासीपल्या बस स्टैंड पर विस्फोटक मिलने के बाद, स्थानीय पुलिस और आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने तुरंत कार्रवाई की। बस स्टैंड के पास प्लास्टिक कवर में छिपी छह जिलेटिन की छड़ें मिलीं, जिससे व्यस्त परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएँ बढ़ गईं। अलर्ट के बाद, कलासीपल्या पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने आतंकवाद निरोधी दस्ते के साथ मिलकर घटनास्थल का दौरा किया और घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया।

'जहां देखों कंगना रनौत को थप्पड़ मारो', कांग्रेस नेता का विवादित बयान, राजनीतिक बवाल शुरू, एक्ट्रेस ने दिया 'थप्पड़' का जवाब

कांग्रेस नेता केएस अलगिरी ने गुरुवार को कहा कि अगर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत तमिलनाडु आती हैं तो उन्हें थप्पड़ मार देना चाहिए। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। केएस अलगिरी ने अपने बयान में कहा कि 'कुछ महीने पहले जब वह एयरपोर्ट गई थीं, तो एक महिला पुलिस अधिकारी ने उन्हें थप्पड़ मारा था। पुलिस अधिकारी ने कहा था कि वह जहां भी जाती है, सभी को गालियां देती है। मैंने किसानों से कहा कि अगर वह हमारे इलाके में आती है तो एयरपोर्ट वाली पुलिस अधिकारी की तरह ही करना। तभी वह अपनी गलती सुधार पाएगी।'

तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व नेता केएस अलगिरी के हाल के बयानों से उनकी पार्टी एक बार फिर मुश्किल में पड़ गई है। केएस अलगिरी ने कहा कि अगर बीजेपी सांसद कंगना रनौत तमिलनाडु आती हैं तो उन्हें थप्पड़ मार देना चाहिए'। उनके तीखे और कठोर शब्दों ने किसानों पर उनके पुराने बयानों से नाराज लोगों और बीजेपी सांसद के बीच तनाव और बढ़ा दिया है।

यह विवाद 2020 के किसान आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। सोशल मीडिया पर खुलकर बोलने वाली कंगना रनौत ने आरोप लगाया था कि एक बुजुर्ग महिला प्रदर्शनकारी को 'वहां बैठने के लिए 100 रुपये दिए गए थे'। इस पोस्ट को अपमानजनक और गलत बताया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया था, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ।

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के दौरान, बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में

कहा था कि एक प्रदर्शन स्थल पर एक बुजुर्ग महिला को वहां बैठने के लिए 100 रुपये दिए जा रहे थे। भारी विरोध के बाद अभिनेत्री ने वह पोस्ट हटा दी।

गुरुवार को अलगिरी ने कहा 'कल 10-15 किसान मेरे पास आए और बताया कि कंगना रनौत ने प्रेस से कहा था कि किसान महिलाएं बेकार ज़मीन पर काम करती हैं... एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि भले ही ये महिलाएं खेतों में काम करती हैं, लेकिन वे बहुत मेहनती और बहादुर हैं और कुछ भी कर सकती हैं... कंगना रनौत ने तुरंत जवाब दिया कि अगर उन्हें 100 रुपये दे दिए जाएं तो वे कहीं भी जा सकती हैं... मैं हैरान रह गया। यह महिला, जो सांसद है, किसान महिलाओं की बुराई क्यों कर रही है? वे ग्रामीण भारत से आती हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों से कहा कि अगर रनौत 'हमारे इलाके' में आती हैं तो उन्हें थप्पड़ मार देना चाहिए, जैसे पिछले साल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ मारा था।

कांग्रेस नेता के जवाब में कंगना रनौत ने कहा कि वह भारत में 'जहां चाहे जा सकती हैं'। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर कुछ लोग मुझसे नफरत करते हैं, तो मुझे प्यार करने वाले लोग भी हैं।' उन्होंने कहा कि 'थलाइवी' में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता का किरदार निभाने के बाद तमिलनाडु में उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। रनौत ने दावा किया कि तमिलनाडु के विपक्षी सांसद भी हाल ही में उन्हें 'थलाइवी' कहकर बुलाते हैं।

एशिया कप 2025 में भारत-ओमान आमने-सामने, अबु धाबी में होगी भिड़ंत

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय टीम एशिया कप 2025 में शुक्रवार को अपना आखिरी लीग मुकाबला शेख जायद स्टेडियम में ओमान से खेलेगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकती है और कुछ खिलाड़ियों को आराम दे सकती है। अभी तक भारत ने दो मुकाबले खेले हैं जिसमें उसे बेहतरीन जीत हासिल हुई है।

हालांकि, रविवार, 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच को देखते हुए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में ओमान के खिलाफ ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। 14 सितंबर को पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में 7 विकेट से मिली करारी शिकस्त के बाद, भारतीय टीम अपने चिर प्रतिद्वंद्वी के साथ एक और मैच जीतने की कोशिश करेगी। कोच गौतम गंभीर के बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं होने के कारण, रिंकू सिंह शायद इस मैच को डगआउट से ही देखेंगे।

हॉलीवुड की सबसे हॉट अभिनेत्रियों में शुमार सिडनी स्वीनी को मिला बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म का ऑफर

हॉलीवुड अभिनेत्री सिडनी स्वीनी को भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक में अभिनय करने का प्रस्ताव मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें इस भूमिका के लिए 530 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने की पेशकश की गई है।

'द सन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक भारतीय प्रोडक्शन

कंपनी ने सिडनी के साथ 45 मिलियन पाउंड (लगभग ?530 करोड़) का सौदा किया है। यह फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्मों में से एक मानी जा रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'इस सौदे में 35 मिलियन पाउंड (?415 करोड़ से ज़्यादा) की फीस और 10 मिलियन पाउंड (?115 करोड़ से ज़्यादा) के प्रायोजन समझौते शामिल हैं। निर्माताओं को उम्मीद है कि सिडनी की स्टार पावर फिल्म को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचाने में मदद करेगी।'

फिल्म में सिडनी स्वीनी एक युवा अमेरिकी स्टार का किरदार निभाएंगी, जिसे एक भारतीय सेलिब्रिटी से प्यार हो जाता है। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की शूटिंग न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन और दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर की जाएगी। यह 2026 की शुरुआत में रिलीज़ होने की उम्मीद है।

सरकार के खजाने में आई 'छप्पर फाड़' दौलत, विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त बढ़त

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 4.7 अरब डॉलर बढ़कर 702.97 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसके एक सप्ताह पहले देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.04 अरब डॉलर बढ़कर 698.27 अरब डॉलर रहा था।

पांच सितंबर को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 2.54 अरब डॉलर बढ़कर 587.01 अरब डॉलर हो गईं। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं में मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल होता है।

केन्द्रीय बैंक के अनुसार, आलोच्य सप्ताह में देश का स्वर्ण भंडार 2.12 अरब डॉलर बढ़कर 92.42 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 3.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.77 अरब डॉलर रहा। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष में भारत की आरक्षित भंडार 90 लाख डॉलर बढ़कर 4.76 अरब डॉलर पहुंच गया।

उम्मीद नहीं थी कि सत्र का अंत ऐसा होगा विश्व चैंपियनशिप में खिताब का बचाव ना कर पाने पर बोले नीरज चोपड़ा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को कहा कि विश्व चैंपियनशिप में आठवें स्थान पर रहना उनके लिए सत्र के अंत की उम्मीद के अनुरूप नहीं था लेकिन वह ब्रेक के बाद दमदार वापसी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछली बार के चैंपियन चोपड़ा गुरुवार को तोक्यो में 84.03 मीटर ही भाला फेंक सके और पांचवें दौर के बाद बाहर हो गए। इस दौरान वह पीठ दर्द से परेशान रहे। उन्होंने बाद में खुलासा किया कि पीठ की समस्या इस महीने की शुरुआत से ही उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन वह इसे अपने खराब प्रदर्शन का कारण नहीं बताना चाहते थे।

उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण कर रहे सचिन यादव की सराहना की, जिन्होंने 86.27 मीटर की शानदार थ्रो के साथ उनसे बेहतर प्रदर्शन किया और चौथे स्थान पर रहे। चोपड़ा ने एक्स पर लिखा, 'मैंने तोक्यो में विश्व चैंपियनशिप के साथ सत्र का इस तरह से अंत करने की उम्मीद नहीं की थी। मैं सभी चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन वह मेरा दिन नहीं था।'

उन्होंने कहा, 'मैं सचिन के लिए बहुत खुश हूं, जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और वह लगभग पदक जीत ही गए थे।' स्वर्ण पदक त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वाल्कोट (88.16 मीटर) को मिला। उनके बाद ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स (87.38 मीटर) और अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन (86.67 मीटर) का स्थान रहा। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता 27 वर्षीय चोपड़ा ने अधिक मजबूती हासिल करके दमदार वापसी करने का वादा किया। उन्होंने कहा, 'आप सभी के समर्थन के लिए आभारी हूं। इससे मुझे दमदार वापसी करने की प्रेरणा मिलती है।'

ग्राहकों को बड़ी राहत, डेबिट कार्ड, न्यूनतम शेष राशि पर आरबीआई ने बैंकों को दिए निर्देश

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को ग्राहकों से ली जाने वाली कुछ फीस कम करने की सलाह दी है। इनमें डेबिट कार्ड चार्ज, लेट पेमेंट पेनल्टी और मिनिमम बैलेंस जैसी फीस शामिल हैं। इस कदम से बैंकों की अरबों रुपए की कमाई प्रभावित हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम से बैंकों की अरबों रुपए की कमाई पर असर पड़ सकता है। आरबीआई का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब बैंक कॉरपोरेट लोन में घाटे के बाद अब रिटेल लोन–जैसे पर्सनल, कार और छोटे बिजनेस लोन–पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इन्हीं से उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है लेकिन तेजी से बढ़ती इस कमाई ने ग्राहकों पर फीस का बोझ भी बढ़ाया है, जिस पर आरबीआई ने ध्यान खींचा है। आरबीआई का कहना है कि ये फीस खासकर गरीब और कम आय वाले ग्राहकों पर बोझ डालती हैं। फिलहाल आरबीआई ने कोई तय सीमा नहीं लगाई है लेकिन बैंकों को पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने को कहा है। ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बैंकबाजार के अनुसार, फिलहाल रिटेल और छोटे बिजनेस लोन पर प्रोसेसिंग फीस 0.5इ से 2.5इ तक है। वहीं, कुछ बैंक होम लोन पर अधिकतम ?25, 000 तक की फीस वसूलते हैं। आरबीआई ने पाया है कि कई बैंक एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग ग्राहकों से अलग-अलग फीस वसूल रहे हैं, जो पारदर्शिता और निष्पक्षता के खिलाफ है। इसी वजह से भारतीय बैंक संघ बैंकों के साथ 100 से ज्यादा रिटेल प्रोडक्ट्स पर चर्चा कर रहा है, जिन पर आरबीआई की कड़ी नजर है।

शिवकाशी में नए डिजाइन के पटाखों की बंपर मांग दिवाली से पहले ही कारोबार में चमक की उम्मीद

चेन्नई **(एजेंसी)**। रोशनी के त्योहार, दीपावली के नज़दीक आते ही, तमिलनाडु के शिवकाशी में, जो आतिशबाज़ी के केंद्र के रूप में जाना जाता है, पटाखों का उत्पादन ज़ोर पकड़ रहा है। शिवकाशी ज़िले के विरुधुनगर स्थित सोनी विनायगा फ़ायरवर्क्स के मालिक अभिषेक ने इस सीज़न की व्यावसायिक बिक्री को लेकर आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसी साल सभी उत्पाद बिक जाएँगे। इस साल कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह पिछले साल जैसी ही है। इस बार कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इस साल सब कुछ अच्छा रहेगा।

इस साल दिवाली सामान्य से पहले आने का ज़िक्र करते हुए, अभिषेक ने कहा कि इस साल दिवाली थोड़ी जल्दी आ गई है। इस साल बिक्री पिछले साल से बेहतर होगी। हमें इस साल ज़्यादा बिक्री की उम्मीद है क्योंकि उत्पादन बहुत कम है। इसलिए, मेरा मानना है कि इस साल सभी उत्पादों की माँग ज़्यादा रहेगी और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस साल अच्छी कमाई करेंगे। इसके अलावा, सोनी विनायगा फायरवर्क्स के प्रबंध निदेशक हरि राम कुमार ने कहा कि कंपनी ने ग्राहकों के लिए नई किस्में पेश करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि लोग हर साल हमसे नए उत्पादों की उम्मीद करते हैं। इस बार, हमने अलग-अलग रंग और डिज़ाइन लॉन्च किए हैं। हम देखेंगे कि हमारे ग्राहक नवीनतम किस्मों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। बिक्री हमेशा अच्छी रही है, और इस साल तुलनात्मक रूप से बेहतर है। इस बीच, निर्माताओं ने इस दिवाली सीज़न में बच्चों के लिए विशेष डिज़ाइन भी पेश किए हैं। जंगल थीम पर आधारित पटाखे भी उपलब्ध हैं, जैसे शेर, भेड़िया और बाघ थीम वाले बक्सों में पैक किए गए पटाखे। इसके साथ ही, सभी उम्र के बच्चों को आकर्षित करने के लिए कार्टून, खेल, संगीत और अन्य थीम पर आधारित पटाखों की कई नई किस्में पेश की जा रही हैं। दूसरी ओर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हाल ही में स्वतः संज्ञान लेते हुए जिले की सभी पटाखा फैक्ट्रियों का तत्काल निरीक्षण करने का आदेश दिया था। इसके बाद, 15 निरीक्षण दल गठित किए गए और 14 जुलाई से निरीक्षण शुरू हुआ। उस दिन से, शिवकाशी, वेम्बकोट्टई और आसपास के इलाकों में चल रही 200 से ज़्यादा फैक्ट्रियों को निरीक्षण के लिए बंद कर दिया गया।

रूसी नागरिकों के लिए खुशखबरी! भारत में कर सकेंगे कैशलेस पेमेंट, मजबूरी में रखते हैं कैश

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। रूस के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्बेरबैंक ने भारत के क्रेडिट मैनेजमेंट ऐप चेक के साथ साझेदारी की है। इस समझौते के तहत अब भारत आने वाले रूसी पर्यटक कैशलेस पेमेंट कर सकेंगे। बैंक द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह कदम दोनों देशों के बीच मोबाइल बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा।

स्बेरबैंक के अनुसार, यह मोबाइल ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपलब्ध है। किसी भी रूसी नागरिक को इस ऐप का उपयोग करने के लिए पासपोर्ट और वैध भारतीय वीजा के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक ने आगे बताया कि वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए रूसी पर्यटकों को भारत में मौजूद पार्टनर एजेंट से मिलना होगा। इसके लिए ऐप के जरिए ही अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है। यह सेवा भारत के सभी बड़े शहरों में उपलब्ध होगी। एक्टिवेशन के बाद, वॉलेट को स्बेरबैंक ऑनलाइन के माध्यम से टॉप-अप किया जा सकेगा।

मध्य रेल
भुसावल मंडल
विद्युतीकरण तथा विभिन्न अन्य कार्य
1) कार्य का विवरणः भाग ए-जालम्ब, नांदुरा और शेगाँव स्टेशनों पर पंपों की आवश्यकता के संबंध में विद्युत कार्य। **भाग बी**-लासलगाँव में पुराने स्टील टैंक के स्थान पर 1 लाख लीटर की आरसीसी ओवरहेड टैंक क्षमता के प्रावधान के संबंध में विद्युतीकरण कार्य। **2) अनुमानित लागतः** ₹ 37,96,533/-. **3) ऑनलाईन बिड सबमिशन का अंतिम दिनांक और समयः** 10/10/2025 को 15.00 बजे। **4) वेबसाइट विवरणः https://www.ireps.gov.in**
व.मं.वि.इं. (सा.)
ई-निविदा सं.: BSL-L-W-T-43-2025
रेलवे फाटक को बंद स्थिति में पार करना मना है
Sai/BSL/11

आर्यन खान के डेब्यू सेलिब्रेशन में नीता अंबानी ने साड़ी से उड़ाए सबके होश, सबकी नज़रें सिर्फ उन्हीं पर थमीं!

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बहुत जल्द ही नेटफ्लिक्स सीरीज से डायरेक्टर के तौर पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। जिसको लेकर खान ने ग्रांड सेलिब्रेशन का आयोजन एनएमएसीसी में हुआ था। यहां पर तमाम बॉलीवुड के तमाम सितारें पहुंचे थे। इस सेलिब्रेशन में नीता अंबानी अपनी फैमिली के साथ नजर आईं। यहां पर बहु श्लोका औ राधिका के साथ मुकेश अंबानी और आकाश अंबानी भी इस सेलिब्रेशन के लिए इनवाइटेड थे। हालांकि, नीता अंबानी ने अपने लुक से सबके होश उड़ा दिए। नीता अंबानी का साड़ी लुक सब पर भारी पड़ गया। ग्रेंड इवेंट में नीता अंबानी ने क्लासी कंटेम्प्रेरी लुक क्रिएट किया है। मनीष मल्होत्रा डिजाइन की हुई जेड ग्रीन कलर की ब्यूटीफुल साड़ी जिसक बॉर्डर पर वर्क था। इसके साथ ही में लैस वाले स्वारोस्की जड़े हाफ स्लीव ब्लाउज ने इसे एखदम रॉयल लुक बना दिया है। नीता अंबानी के मेकअप लुक की बात करें, तो उन्होंने ग्लॉसी चिक्स, न्यूड ब्राउन लिपस्टिक, वेवी साइड पार्टीशन हेयर किए।

नीता अंबानी ने जेड ग्रीन साड़ी के साथ ही मैचिंग फूलों वाले चोकर नेकपीस पहना है, जिसने इवेंट में अटैंशन बढ़ा दी। इसके साथ ही उन्होंने हार्ट शेप वाले रेयर डायमंड से बने इस नेकलेस के साथ साइड में बना फ्लावर भी किसी जादू से कम नहीं है, यह टर्क्वाएज टाइटेनियम से जड़ा हुआ है। नीता अंबानी का यह महारानी लुक बेहद ही प्यारा लग रहा है।

इसके अलावा, नीता अंबानी की छोटी बहू राधिका मर्चेंट फैमिली के साथ इवेंट में पहुंची। इस इवेंट में राधिका ने मरून शेड की फ्रंट स्लिट ड्रैस पहन रखी है। राधिका ने डायमंड नेकपीस और

उम्मीद है कि एशेज के पांचों टेस्ट में खेलूंगा : पीठ की समस्या से जूझ रहे पैट कमिंस ने दिया बयान

सिडनी **(एजेंसी)**। पीठ की समस्या से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज पैट कमिंस एशेज के सभी पांच टेस्ट मैचों में खेलना चाहते है। कमिंस ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। खेल क्लबों के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बने रहने के लिए संघीय सरकार ने 50 मिलियन डॉलर के अनुदान की घोषणा की गई।

कमिंस ने स्वीकार किया कि एशेज से पहले वह पूरी तरह से प्रतीक्षा करने और देखने की स्थिति है। कमिंस ने कहा, 'लक्ष्य पांच टेस्ट मैच है। हर गर्मियों में आप पांच टेस्ट मैच खेलने का लक्ष्य रखते हैं। यह मैच थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि आप बाकी मैचों से थोड़े अलग अंदाज में आ रहे हैं। लेकिन शुरुआती लक्ष्य पांच विकेट लेना है। एक बार जब हम करीब पहुंच जाएंगे, तो हम शायद अधिक यथार्थवादी परिस्थितियों पर बात करेंगे। सच कहूं तो यह कहना अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन फिलहाल हमारा लक्ष्य इन सबके लिए तैयार रहने का प्रयास करना है।' कमिंस ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि पहले तीन टेस्ट मैचों के कार्यक्रम में आठ दिनों का

स्पष्ट अंतराल रखा गया था, इसलिए बैकअप लेना कोई समस्या नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह संभावना नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया पूरी गर्मियों में एक अपरिवर्तित आक्रमण के साथ टिकेगा। उन्होंने कहा, 'ज्यादातर सालों में, कम से कम एक गेंदबाज तो खेल ही जाता है। जॉश हेजलवुड पिछले साल आखिरी हाफ में नहीं खेल पाए थे। जाहिर है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बस एक नए गेंदबाज की जरूरत है, जो आकर टेस्ट मैच में बिना पलक झपकाए 40 ओवर गेंदबाजी कर सके।' उल्लेखनीय है कि इस हफ्ते ऑस्ट्रेलियाई कोच एंड्रयू मैकडॉनाल्ड ने कहा कि कमिंस इस सीरीज में 'हिस्सा' लेंगे। इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच 21 नवंबर से पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होगा। इस साक्षात्कार में बाद में मैकडॉनाल्ड ने यह भी कहा कि कमिंस एशेज में 'महत्वपूर्ण' भूमिका निभाएगे।

पश्चिम रेलवे
वडोदरा मंडल
मैन्युअल रूप से TSR (P) 55.000 KMS द्वारा TRT. 2.546 KMS एवं ट्रैक रिन्युअल कार्य
ई–निविदा सूचना सं.
DRM-BRC 123 OF 2025-26
भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए मंडल रेल प्रबंधक (W A/C), पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा–390 004 द्वारा निम्नानुसार कार्यों हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । **कार्य का नामः** वडोदरा डिविजन :– वरि. DEN पूर्व BRC के क्षेत्राधिकार आधिन मैन्युअल रूप से TSR (P) 55.000 KMS द्वारा TRT. 2.546 KMS एवं अन्य सहायक ट्रैक रिन्युअल कार्य । **कार्य की अनुमानित लागत (₹ में):** 17,69,54,559.12 **जमा कराने की बीड सुरक्षा (₹ में):** 10,34,800.00 **निविदा जमा कराने एवं निविदा खोलने की तिथि एवं समयः** निविदा दिनांक **10.10.2025** को 15:00 बजे से पहले जमा की जाएगी एवं उसी दिनांक को 15:30 बजे निविदा खोली जाएगी । **वेबसाईट का विवरण एवं नोटीस का स्थान जहाँ से विवरण देखे जा सकते हैं एवं कार्यालय का पता जहाँ से निविदा प्रपत्र खरीद सकते हैं: वेबसाईटः www.ireps.gov.in** मंडल रेल प्रबंधक (W A/C), पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा–4
BRC-194
हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा रिस्पॉन्स बल वाहिनी मुख्यालय भवन का किया उद्घाटन

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना जिला के बिहटा में राज्य आपदा रिस्पॉन्स बल (एस0डी0आर0एफ0) वाहिनी मुख्यालय के नये भवन का शिलापट्ट अनावरण एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात् मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित भवन एवं पूरे परिसर का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा रिस्पॉन्स बल द्वारा बाढ़ एवं आपदा के समय किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही वहां लगाई गई प्रदर्शनी में आपदा के समय उपयोग किए जानेवाले उपकरणों / साधनों की कार्यपद्धतियों के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित जवानों की हौसलाअफजाई की और कहा कि आपलोग इसी तरह अच्छे से काम करते रहिए।

ज्ञातव्य है कि राज्य में बाढ़, आगजनी, भूकंप, चक्रवात, नदी में डूबने की घटना आदि आपदा के दौरान खोज, बचाव एवं राहत कार्यों के लिए राज्य आपदा रिस्पांस बल (एस0डी0आर0एफ0) का गठन एक विशेष प्रशिक्षित बल के रूप में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।

इसके बटालियन के मुख्यालय हेतु बिहटा, पटना में राज्य सरकार के द्वारा 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। बटालियन के अधिकारियों तथा जवानों के आवासन तथा कार्यालय हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2013 में अस्थायी पोटा केबिन का निर्माण किया गया। इन अस्थायी संरचना के काफी पुराना हो जाने पर तथा एस0डी0आर0एफ0 के कार्यबल में बढ़ोतरी के कारण वहाँ आवासन एवं कार्यालय कार्य के संचालन में काफी कठिनाई हो रही थी इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर एस0डी0आर0एफ0 के अधिकारियों एवं जवानों के बेहतर आवासन, प्रशिक्षण एवं कार्यालय हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 267.24 करोड़ रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी तथा निर्माण की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग को दी गयी।

इस योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 30 अप्रैल, 2023 को किया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा कई बार स्थल पर जाकर निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया गया। 11 जुलाई, 2025 को निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना को शीघ्र पूरा करने, छतों पर सोलर लगाने तथा परिसर के पहुँच पथ को ठीक करने का निर्देश दिया गया।

आज उद्घाटन किए गए भवनों में 04 मंजिला प्रशासनिक भवन है जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के लिए कार्यालय कक्ष का निर्माण कराया गया है। 03 मंजिला प्रशिक्षण भवन है जिसमें 06 स्मार्ट क्लास रूम, पुस्तकालय, सभाकक्ष तथा कम्प्यूटर लैब, फैकल्टी चैम्बर एवं कार्यालय कक्ष है। 03 मंजिला क्वार्टर मास्टर स्टोर है जिसमें कुल 05 बड़े-बड़े भण्डार कक्ष हैं जिसमें आपदा से जुड़े आवश्यक उपकरण नाव आदि रखे जाएंगे। 03 मंजिला क्यू0आर0टी0 भवन है जिसमें बहुउद्देशीय हॉल, डॉरमेट्री, डायनिंग हॉल आदि हैं। राज्य आपदा रिस्पांस बल के कर्मियों के आवासन हेतु 03 बैरक का निर्माण किया गया है। एक बैरक में 100 लोगों के रहने की व्यवस्था है, इस प्रकार 03 बैरक में कुल 300 लोग रह सकते हैं। हेड कांस्टेबलों एवं कास्टेबलों के आवासन हेतु बहुमंजिले भवन में कुल 132 यूनिट फ्लैट बनाये गये हैं। ऑफिसर्स मेस में कुल 06 गेस्ट रूम, मीटिंग रूम तथा डाइनिंग हॉल हैं। कमान्डेंट, डिप्टी कमान्डेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर तथा डॉक्टर के आवासन हेतु अलग-अलग भवनों का निर्माण किया गया है।

डॉ जी एस तोमर आरोग्य भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने

कोच्चि। कोच्चि केरल में आयोजित आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रो.(डॉ.) गिरीन्द्र सिंह तोमर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नामित किया गया है । यह घोषणा आरोग्य भारती की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राकेश पण्डित जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह डॉ कृष्ण गोपाल जी, आरोग्य भारती के संरक्षक डॉ प्रवीण भावसार, कार्याध्यक्ष डॉ बी एन सिंह, राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉ अशोक कुमार वार्ष्णेय जी एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में की ।

पूर्णिया में बवाल, मूर्ति तोड़फोड़ के बाद जमकर हुआ हंगामा, 12 लोग गिरफ्तार; गांव छावनी में तब्दील

पूर्णिया। पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड के मजगामा गांव में एक निर्माणाधीन मूर्ति में तोड़फोड़ मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक मूर्ति को खंडित करने वाला और 11 उपद्रव करने वाले शामिल हैं। पहुंचकर बचाया और हिरासत में लिया। इसी बीच पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई। डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल के अनुसार, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को चार राउंड फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान ओम प्रकाश नाम का एक युवक घायल हुआ

फिलहाल गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात है। पूर्णिया डीएम अंशुल कुमार और एसपी स्वीटी सहरावत मौके पर कैंप कर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। वहीं क्षतिग्रस्त मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है।

घटना के दौरान उपद्रव और बवाल भी हुआ। भीड़ ने एक युवक को पकड़कर पिटाई कर दी, जिसे पुलिस ने मौके पर है, जिसका इलाज जीएमसीएच पूर्णिया में चल रहा है।

हंगामे के दौरान उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी भी की, जिसमें एक दुकान को नुकसान पहुंचा। सूचना मिलते ही डीआईजी, डीएम, एसपी और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया। वर्तमान में गांव में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस कैंप कर रही है।

नेपाल की नई अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, विदेश मंत्रालय ने कहा- मिलकर काम करना जारी रखेंगे

नई दिल्ली। नेपाल के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आपने इस मामले पर पहले जारी किया गया हमारा बयान देखा होगा। हम नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने नेपाल की प्रधानमंत्री कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के लिए भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। एक घनिष्ठ पड़ोसी, एक लोकतंत्र और एक दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में भारत हमारे दोनों देशों के लोगों और लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।

पीएम मोदी ने बीते दिनों नेपाल की अपनी समकक्ष सुशीला कार्की से बात की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कार्की के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने पड़ोसी देश में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई जनहानि पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती सुशीला कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। हाल ही में हुई जनहानि पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की।

उन्होंने कहा साथ ही मैंने उन्हें और नेपाल की जनता को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं।'' काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार बातचीत के दौरान कार्की (73) ने कहा, 'अंतरिम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता चुनाव ही रहेंगे, तथा जवाबदेह, उत्तरदायी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए दृढ़ संकल्प युवाओं की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा।

योगी आदित्यनाथ का दावा : किसानों को मिल रहा उपज का पूरा मूल्य, योजनाएं बदल रहीं तकदीर

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव के दौरान किसानों के कल्याण में सुधार पर प्रकाश डाला। अपने भाषण में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अब उनकी उपज का भुगतान मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी विभिन्न सामाजिक बीमा योजनाओं के माध्यम से किसान अपने ऋण चुकाने में सक्षम हो रहे हैं।

आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, सरकार द्वारा दिए गए 6, 000 रुपये के माध्यम से 11 करोड़ किसान साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो गए हैं।' उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मिशन रोज़गार जैसी स्टार्टअप योजनाओं ने युवाओं के जीवन को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को उनकी सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने का काम किया गया है। मिशन रोज़गार, स्टार्टअप और स्टैंडअप योजनाओं ने युवाओं के जीवन को बदल दिया है... आज, भारतीय युवा नौकरी चाहने वाला नहीं है; वह नौकरी देने वाला बनने की क्षमता रखता है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि रेडीमेड गारमेंट्स का व्यवसाय स्थापित करके महिलाएँ आत्मनिर्भर बन रही हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। योगी ने कहा, 'हज़ारों बहनें रेडीमेड गारमेंट्स के ज़रिए आत्मनिर्भरता की राह पर चल रही हैं

व्यापार डील के लिए ट्रंप ने चली बड़ी चाल! क्या ताइवान बनेगा 'बलि का बकरा'?

ताइपे **(एजेंसी)**। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ एक बड़े व्यापार समझौते को लेकर अपनी उत्सुकता दिखाई है। इसी सिलसिले में उन्होंने ताइवान को दी जाने वाली तकरीबन ?3, 340 करोड़ की सैन्य सहायता रोक दी है, जिससे ताइवान पर चीन का दबाव और बढ़ने की उम्मीद है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब अमेरिका और चीन के बीच एक जटिल व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने ताइवान के लिए सैन्य सहायता पैकेज को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इस पैकेज में गोला-बारूद और अत्याधुनिक ड्रोन शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार यह फैसला भविष्य में बदला भी जा सकता है। यह कदम ट्रंप की 'लेन-देन वाली विदेश नीति' को दर्शाता है। उनका मानना है कि सहयोगी देशों को अपनी सुरक्षा पर खुद खर्च करना चाहिए, न कि अमेरिकी सहायता पर निर्भर रहना चाहिए। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ताइवान को अमेरिकी हथियार खरीदने चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें मुफ्त में दिया जाए।

चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और लगातार उस पर सैन्य दबाव बनाए हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन लगभग हर दिन अपने युद्धपोत और विमान ताइवान के आसपास के समुद्री और हवाई क्षेत्र में भेजता है। दिसंबर 2024 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था, 'ताइवान और चीन के लोग एक ही परिवार हैं। कोई भी हमारे रिश्तों को नहीं तोड़ सकता।' जवाब में ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने हाल ही में रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान किया है। उनकी सरकार ने और अधिक ड्रोन व जहाज खरीदने के लिए विशेष फंड को मंजूरी दी है, ताकि अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाया जा सके। ट्रंप का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता चल रही है। ट्रंप के लगाए टैरिफ के जवाब में चीन ने भी जवाबी टैरिफ लगाए थे, जिससे अमेरिकी किसान दबाव में आ गए। चीन, अमेरिका के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 25इ खरीदता रहा है, लेकिन उसने अमेरिका से खरीद बंद कर दी और ब्राजील से आयात बढ़ा दिया है। इस आर्थिक दबाव ने ट्रंप को चीन के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए मजबूर किया है। ट्रंप जल्द ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करने वाले हैं। इस बातचीत में टिक-टॉक जैसे चीनी ऐप्स पर पाबंदी और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ऐसे में ताइवान की सहायता रोकना शी जिनपिंग को खुश करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

भारत के रेयर अर्थ की भयंकर डिमांड चीन के सबसे बड़े दुश्मन ने दिया तगड़ा ऑफर

बीजिंग। **(एजेंसी)**। एक ऐसी डील जिसने पूरे एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। चीन के सबसे बड़े दुश्मन ताइवान ने भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया है जो आने वाले समय में ऊर्जा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा निर्माण तक भारत को पूरी तरह से बदल सकता है। रेयर अर्थ मिनिरल्स यानी दुर्लभ खनिजों के जरिए भारत को एक तरफ सेमीकंडक्टर बनाने की ताकत मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन का एकाधिकार भी टूट रहा है। भारत और ताइवान की ये दोस्ती सिर्फ आर्थिक सौदा नहीं बल्कि एक रणनीतिक गेमचेंजर भी साबित होगा।

चीन परमानेंट मैगनेट, और रेयर अर्थ मिनिरल्स में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस और ऊर्जा सेक्टर हर जगह इसकी जरूरत है। इस साल की शुरुआत में चीन ने सप्लाई चेन रोक दी थी। दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका से यूरोप तक सभी देश बैकअप तलाशने लगे। चीन के पास सबसे

ज्यादा भंडार है और टेक्नोलॉजी भी वहीं है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ मिनिरल्स का आंकड़ा हालाकिं चीन औ? ब्राजील से कम है। लेकिन रूस, अमेरिका, वियतमान, ग्रीनलैंड से बहुत ज्यादा है।

रेयर अर्थ मिनिरल्स स्थायी चुम्बकों की रीढ़ हैं, जो उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चीन ने इस वर्ष की शुरुआत में दुर्लभ मृदा चुम्बकों की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करके वैश्विक चिंता पैदा कर दी थी। बीजिंग दुनिया के अधिकांश भंडारों को नियंत्रित करता है और शोधन एवं उत्पादन तकनीक पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका है। रत में अनुमानित 6.9 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ मृदा भंडार है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, जो केवल चीन और ब्राज़ील से पीछे है। महत्वपूर्ण भंडार वाले अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, रूस, वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रीनलैंड शामिल हैं। स संसाधन के बावजूद, भारत ने अभी तक खनिजों को चुम्बकों में संसाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर तकनीक विकसित नहीं की है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला असुरक्षित बनी हुई है।

नई दिल्ली अब इस कमी को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है। खान मंत्रालय के माध्यम से, यह महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए काम कर रहा है।

पाकिस्तान में दहशत का डबल अटैक! दो बम धमाकों में 8 की मौत, मच गया हाहाकार

इस्लामाबाद **(एजेंसी)**। पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में कुछ ही घंटों के अंतराल पर दो बड़े कार बम विस्फोट हुए हैं जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। इन धमाकों में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 23 अन्य घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन शक की सुई पाकिस्तानी तालिबान और बलूच अलगाववादियों की ओर घूम रही है। पहला विस्फोट बलूचिस्तान प्रांत के तुर्बत जिले में हुआ। पुलिस अधिकारी इलाही बख्श ने बताया कि एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी कार को सुरक्षा बलों के काफिले से टकरा दिया। इस हमले में 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 23 लोग घायल हो गए। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई।

पहले हमले के कुछ घंटों बाद दूसरा कार बम विस्फोट दक्षिण-पश्चिमी शहर चमन में हुआ जो अफगानिस्तान की सीमा के पास है। सरकारी प्रशासक इम्तियाज अली के अनुसार इस हमले में 6 लोग मारे गए। इस दोहरे हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से आतंकी हमलों में तेजी आई है खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में। ये दोनों ही क्षेत्र अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक

जून में पाकिस्तान में 78 आतंकवादी हमले हुए थे। बलूचिस्तान में लगभग दो दशकों से अशांति है। यहां के स्थानीय जातीय समूह आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तानी सरकार प्रांत के प्राकृतिक संसाधनों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है जिससे उनके बीच असंतोष बढ़ा है। हाल ही में बलूच विद्रोहियों ने भी कई बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था जिसमें 45 आतंकी मारे गए थे जबकि 19 सैनिकों की भी मौत हुई थी। ये आतंकी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करता रहेगा।

पेंसिल्वेनिया में तीन पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या, 2 घायल, आरोपी ढेर

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। अमेरिका के पेनसिल्वेनिया प्रांत में घरेलू विवाद की जांच करने पहुंचे पुलिस टीम पर एक व्यक्ति ने गोलीबारी की। इसमें 3 पुलिस अफसरों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। यह घटना फिलाडेल्फिया से करीब 185 किमी पश्चिम में स्थित नॉर्थ कोडोरस टाउनशिप में हुई। पुलिस के अनुसार, घरेलू विवाद मंगलवार को शुरू हुआ। इसकी जांच के सिलसिले में पुलिस टीम बुधवार (अमेरिकी दिन के अनुसार) को मौके पर पहुंची, तभी अचानक फायरिंग शुरू हो गई। मामला जांच में होने से हमलावर और घरेलू विवाद से जुड़े लोगों की पहचान उजागर नहीं की गई है। पेनसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने घटना पर दुख जताया है। इस घटना से इलाके के स्कूलों में एहतियातन 'शेल्टर-इन-प्लेस' घोषित किया था। यानी स्कूलों में कोई आ-जा नहीं सकता।

घटना के तुरंत बाद, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने पुलिस के खिलाफ हिंसा को 'हमारे समाज पर एक अभिशाप' बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए संघीय एजेंट घटनास्थल पर मौजूद हैं। पेंसिल्वेनिया के उपराज्यपाल ऑस्टिन डेविस ने एक अलग सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'कृपया यॉर्क काउंटी में हुई गोलीबारी में शामिल अधिकारियों और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करें। इस बीच, पेंसिल्वेनिया के अटॉर्नी जनरल डेव संडे ने कहा कि वह भी घटनास्थल पर जाएँगे। अपनी पोस्ट में इस घटना के मद्देनजर, स्थानीय स्कूल ज़िले ने आश्रय-स्थल आदेश जारी किया,

पहले जैश, फिर लश्कर आतंकियों के कबूलनामे पर बोला भारत

पाक सेना-सरकार और टेररिस्ट के नेक्सेस से दुनिया अवगत

इस्लामाबाद **(एजेंसी)**। पाकिस्तान के आतंकी अब एक एक कर खुद ही अपने मुल्क की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान आतंक का निर्यातक देश और दहशतगर्दों का सबसे मुफीद ठिकाना भी है। जैश-ए-मोहम्मद (वश) के एक कमांडर द्वारा मसूद अज़हर के बहावलपुर कैंप से संबंध होने के पाकिस्तान के दावे का पर्दाफ़ाश करने के कुछ दिनों बाद, लश्कर-ए-तैयबा के एक सदस्य ने स्वीकार किया है कि मुरीदके स्थित मरकज़ तैयबा स्थित आतंकी समूह के मुख्यालय को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत नष्ट कर दिया था।

पाकिस्तान और आतंकवाद पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम सभी को सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद से लड़ना होगा... हम दुनिया से आह्वान करते हैं कि हमें आतंकवाद से निपटने के लिए अपने प्रयासों को तेज करना होगा। पाकिस्तान से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के हालिया वीडियो पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद के मामलों में, हम स्पष्ट हैं कि दुनिया आतंकवादियों

और पाकिस्तानी सरकार तथा सेना के बीच गठजोड़ से अवगत है। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित एक वीडियो में, लश्कर कमांडर कासिम ने स्वीकार किया कि मुरीदके आतंकी कैंप, जिसे 7 मई के ऑपरेशन में नष्ट कर दिया गया था, को 'पहले से भी बड़ा' बनाया जा रहा है। मुरीदके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शेखपुरा ज़िले का एक शहर है। वीडियो में निर्माणाधीन स्थान के सामने खड़े कासिम कहता है कि मैं मुरीदके में मरकज़ तैयबा के खंडहरों पर खड़ा हूं, जो (भारतीय) हमले में नष्ट हो गया था। इसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। ईश्वर की कृपा से यह मस्जिद पहले से भी बड़ी बनेगी।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)